उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : सदन की कार्यवाही दोपहर के भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थागित की जाती है।

The House adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock—THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P.K. JOGI) in the Chair.

SHORT DURATION DISCUSSION

Deteriorating Law and Order Situation in Utter Pradesh—Contd.

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : सैयद सिब्ते रजी जी।

सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) : वाइसचेयर्मैन साहब; इससे पहले कि मैं अपनी बात रखू मै समझता हूं कि प्रारम्भ में ही इस बात को साफ कर दूं कि जब हम इस परिचर्चा में राज्यपाल महोदय का नाम लेते हैं तो हमारा तात्पर्य राज्यपाल पर व्यक्तिगत आक्षेप से ताल्लुक नही रखता है क्योकि हम राज्यपाल को कांस्टिटयूशन के उन प्रावधानों के तहत यहां डिसकस नही कर रहे है जिनके तहत हम उस हाई आफिस पर कुछ बातचीत नही करते। लेकिन आज जो हम यहां पर चर्चा कर रहे है क्योकि वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 396(I) (ए), (बी) और (सी) का अगर खुलासा किया जाए....

मै सदन का अधिक समय नही लेना चाहूंगा कि उन प्रावधानों को आप के सामे प्रस्तुत करूं । स्वयं आप उसे भलीभांति जानते है कि जब हम राज्यपाल का नाम लेते है और वहां आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो प्रोक्लेमेशन की घोषणा करते ही सारी-की-सारी एक्जीक्यूटिव पावर्स या एक्जीस्यूटिव फंक्शंस की जितनी भी जिम्मेदारियां और अधिकार है, वह राष्ट्रपति के हाथों मे निहित हो जाती हो जाती है और जब राष्ट्रपति के हाथों में शाक्तियां निहित हो जाती है तो निश्चित रूप से हमार जो फेडरल सिस्टम है या पार्लियामेंतरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उस में जब-जब हम राष्ट्रपति का नाम लेंगे या राष्ट्रपति शासन का नाम लेगे या राज्यपाल का नाम लेंगे तो हमार तात्पर्य केन्द्र सरकार से होगा क्योकि केन्द्र सरकार ही आर्टिकल 356 के अंतर्गत वहां पर शासन चला रही होती है। यह सही है कि राज्यपाल उस का एक माध्यम होता है, उस का एक प्रतिनिधि होता है। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में अभरकर आई है, मैं समझता हू कि मुख्य रूप से केन्द्र सरकार उस की जिम्मेदार है । यदि केन्द्र सरकार ने पूर्ण रूप से वहां के शासन में, प्रशासन में दिलचस्पी ली होती तो आज यह परिस्थिति नही पहुंचती कि गवर्नर साहब किसी गलतफहमी के कारणवश या जाने अनजाने में सविधान के ये जो अनुच्छेद है, संविधान के जो आर्टिकल्स या प्रोवीजंस है, उन को या तो वह भूल गए है या उस की अनदेखी कर रहे है और यह समझ बैठे है कि शायद वहां पर किसी एक व्यक्ति विशेष का शासन है या एक विशेष राजनीतिक पार्टी का शासन है या जो संयुक्त मोर्चा है, उस का शासन है जबकि असल में वहां पर इस वक्त शासन केन्द्र सरकार का है । इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, हम सब चिंतित हो गए जब लोक सभा में हमारे गृह मंत्री जी ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन इस हद तक पहुंच चुका है, वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति इस हद तक खराब हो गयी है कि वह अनार्की, डिवास्टेशन और बर्बादी की तरफ पहुंच जाएगा । इस से हम सभी आहत हुए और हम सब को एक धक्क लगा और निश्चित रूप से जब हम मे हमारे प्रदेश की एसी स्थिति पर परिचर्चा कराने की बात की तो हमारे जेहन के अंदर माननीय गृह मंत्री जी का यह वक्तव्य था। हमें खेद है कि ससंदीय प्रणाली के अतंर्गत जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों से आज जो केन्द्र सरकार वहां पर शासन कर रही है और उन के जो प्रतिनिधि वहां पर बैठे हुए हैं, वह हमें इस से वंचित करना चाहती हूं । उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी की टिप्पणी के ऊपर प्रेस कांफरेंस के जरिए वक्तव्य महा-महिम राज्यपाल महोदय ने, उन की जो एक्जीक्यूटिव पोजीशन है, उस का इस्तेमाल करने हुए किया, उससे हम सभी आहत हुए और यह जो पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की महान परपंराए हैं या फेहरल सिस्टम की परंपराएं है, उन पर उस वक्त काफी चोट पहुंचती है ।

महोदय, अभी जैसाकि तबसरा हमारे लायक दोस्त ने किया कि पायोनियर न्यूज पेपर में कल या परसों छपा है, कि गृह मंत्री जी तो जानते ही नहीं है, कि उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? उन के पास फैक्टस् नहीं है, फिगर्स नहीं

है और जो भी वह कह रहे हैं, उसे राष्ट्र भ्रमित हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह जो हमारा 48 साल का लोकतंत्र या गणतंत्र का जीवन है, उस के अंदर पहली बार ऐसा सुना गया है कि केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि अपनी ही सरकार , अपने ही अगुआ और मुखिया को कहे कि उन के पास इतना नही है। अब किसी की गलती मानी जाए। क्या गलती मानी जाए राज्यपाल महोदय की कि केन्द्र सरकार को समय-समय पर जो उन की जिम्मेदारी है, वहां के हालत पर रिपोर्ट करते रहने की, रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं या वह रिपोर्ट कर रहे हैं तो गृह मंत्रालय उसके ऊपर तकज्जों नही कर रहा है, उस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है ? यह इस प्रकार की विरोधाभास की स्थिति आकर खड़ी हो गयी है। महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी यहां पर हैं, वह हमें बताएं कि असल में स्थिति क्या है? आज हमारी विधयिका की जो जिम्मेदारी है, वह भी ससंद में आहूत हो जाती है जबकि वहां ऐसी परिस्थिति आती है कि आर्टीकल 356 का इस्तेमाल होता है। महोदय, पहले यह परपरा थी कि जो भी विधायी कार्य होते थे, वह यहां पर रखे जाते थे। और उन विधायी कार्यो को देखने के लिए एक समिति बनती थी, एक कमेटी बनती थी... जिसमें दोनों सदन के मैम्बरान हुआ करते थे और वे नजर रखते थे कि क्या विधायियका का कार्य जरूरी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मुझे खेद है कि – अभी तक उस तरह की कमेटी नहीं बनी है।

महोदय, यह केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को बड़ा लाइटली ले रही है। मैं यह आरोप लगाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रदेश है , जिसकी लंबाई और चौड़ाई न जाने कहां से कहां तक पहुंचती है, इसकी अपनी विभिन्न समस्याएं है , यह वही प्रदेश है जिसने देश को आठ प्रधानमंत्री दिए हैं, देश के विकास में, देश की प्रगति में उत्तर प्रदेश का अपना ही योगदान है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम भूखें है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी महिलाओं के साथ तरह तरह की नाजायज हरकतें हो रही है। मैं इन आंकडों में नहीं जाना चाहता कि कितने लोग मारे गए एक महीने में, 45 दिन में, 900 लोग मारे गए या कि 925 लोग मारे गए या यह प्रतिशत पिछले साल से कम है, या ज्यादा है। यह इसांनी जिदंगियों के साथ आंकडों के स्टेटिस्टिक्स के जरिए मैं नहीं जाना चाहता कि अभी हमारी वह हालत नहीं बनी है, जो पिछले साल थी। मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। देखना तो यह होगा कि पब्लिक परसेप्शन क्या है। लोग आज केन्द्रीय शासन के बारे में या राज्यपाल महोदय के जरिए जो वहां शासन चलाया जा रहा है केन्द्र शासन की शक्ति लेकर, उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? आज वहां सारी जनता त्राहि-त्राहि कर रही है।

महोदय, अभी यहां पर बात आई कि राज-भवन में हैलेपैड क्यों बनाया जा रहा है, राज-भवन को क्यों सजाया जा रहा है? यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसको हम उठाने जा रहे हैं। हैलीपैड बनते हैं, बिगडतें है, राज-भवन की फर्निशिंग होती है, नहीं होती, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी एप्रोच क्या है? यह कहना राज्यपाल महोदय का, कि हमने हैलीपैड इसलिए बनवाया है, कि काफी खर्चा होता था और उससे पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था, आज हमने सोच लिया। यह सोच का सवाल नहीं है, यह प्रवृत्ति का सवाल है, मानसिकता का सवाल है। पहले भी हमारे राज्यपाल महोदय जो वहां हुआ करते थे, वे सोच सकते थे कि वहां हैलीपैड होना चाहिए। जब हमारे यहां स्थिति ऐसी है कि हमारे विकास का काम रूका हुआ है, हमारा प्रगति का काम रूका हुआ है, हमारी पंचवर्षीय-योजना पिछड़ गई है, हमारी एक साल की जो योजनाएं होती है, वह पिछड़ गई हैं, हमारी जो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए केन्द्र के लिहाज से उसमें उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है, गेहूं नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिल रहा है जलाने का. लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, अनएम्पलायमेंट है, माफिया गिरोह एक दूसरे से लड़ रहे हैं, राजनैतिक उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, बहू-बेटियों की इज्जत पूरी तरह महफूज नहीं है, रातो को लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, राजनैतिक हत्याएं हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में यदि यह हैलीपेड बनाने की बात आती है तो यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।

महोदय, बुनियादी तौर पर जो प्रवेश का मुखिया होता है, प्रदेश की तरफ से जो काम करता है, उसको ऐसा होना चाहिए जैसे कि वे लोग बैठे हुए हैं इस सरकार में जो बार बार कहा करते थे – हाई थिंकिग होनी चाहिए और सिम्पल लिविंग होना चाहिए। आज लोहिया साहब के मानने वाले लोग सरकार में बैठे हैं, जिन्होंने कदम कदम पर यह उपदेश दिया था, देश को यह बताया था, अपनी राजनीतिक पार्टी को बताया था, कि हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, जो जनता के आचरण से मिल सके, जो हमारी जिंदी है उसके अदंर जनता की जिंदगी की झलक आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगता।

लगता यह है कि जैसे वहां कोई आटोक्रेट बैठे हुए है, जैसे कोई तानाशाह बैठे हुए है। राज-भवन के दरवाजे जनता के लिए आज बंद हो गए हैं। जनता की बात तो क्या कहिए, जैसा मैंने पहले कहा था, जन-प्रतिनिधि जो है उनका वहां महत्व नहीं है। एक, दो, चार, पांच जन-प्रतिनिधि अगर कॉकस बना लें या मुखिया को घेर लें, तो मैं समझता हूं कि यह परिस्थिति जो है वह कोई बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है । राज्यपाल जी को या केन्द्र सरकार को मुख्य रूप से वहां पर जो हालात है उनकी तरफ तवज्जुह देनी चाहिए ।

महोदय, यह जो बयान आए हैं बार बार गृह मंत्री के खिलाफ या गृह मंत्री कुछ और स्टेटमेंट दिया उत्तर प्रदेश के खिलाफ, इससे कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनती है । हाई आफिस पर हम यहां पर बहस कर सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, तो हम उस हाई आफिस पर बहस नहीं कर रहे हैं बल्कि उस हाई आफिस में जो बैठा हुआ है वह पद की गरिमा पद की प्रतिष्ठा. पद के व्इकबाल, राज-भवन की परंपराए , राज-भवन के इम्पेक्ट, राज भवन के इकबाल, को जो हैं । गिरा रहा है तो कैसे हम इस बात की तवज्जुह सेंट्रल गवनरमेंट की तरफ न लाएं । हमारा व्यक्तिगत रूप से उनसे कोई झगड़ा नहीं है, हमारा व्यक्तिगत उनके खिलाफ कोई एतराज नहीं करते, लेकिन हमारा यह फर्ज बनता है कि हम केन्द्र सरकार से कहे कि वह चुप्पी तोड़े और बोले । वह बताएं कि आखिर, वहां क्या हो रहा है।

क्या ऐसे ही हमारा उत्तर प्रदेश चलेगा? वहां पर तरह-तरह की समस्याएं बड़ी होती चली जा रही हैं? और यह बदकिस्मती हमारे उत्तर प्रदेश की पिछले सात-आठ साल से चल रही है । अगर कोई यह कहे कि यह एक आदमी की वजह से है या एक पार्टी की वजह से है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं । उत्तर प्रदेश में कांग्रसे का शासन जाने के बाद आज एक अस्थायित्वव की परिस्थिति आ गई है। बडे-बड़े लोग जो सत्ता में पहुंचते हैं, वे ऐसी गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन करते हैं जिससे कानून और व्यवस्था पर असर पड़ता है । तो ऐसी परिस्थिति में एक ही विकल्प रह जाता है कि केन्द्र सरकार यह देखे कि उनका प्रतिनिधि कहां पर गलत है? गलत कार्य कर रहा है, निरंकुश हो रहा है तो उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए ? यदि वहां विधान सभा नहीं है तो उसका मतलब यह नहीं है कि एकाउंटेब्लिटी नहीं है । आज उत्तर प्रदेश के करोड़ो-करोड़ों लोग नौकरशाही से दबे चले जा रहे हैं , एक ऐसी भावना से दबे चले जा रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, उन पर कुप्रभाव पड़ रहा है,कि किसी की कोई जवाबदेही ही नहीं है । हम जो चाहें करें, यहां पर तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, यहां पर तो केन्द्र सरकार का शासन है, ऐसी परिस्थति अच्छी नहीं है । यदि विधान सभा इस समय वहां नही है तो केन्द्र सरकार का शासन है, ऐसी परिस्थिति अच्छी नहीं है। यदि विधान सभा इस समय वहां नहीं है तो केन्द्र में हमारी जो ससंद है, उसके अंदर हमारी सरकार की जवाबदेही बनती है । इसलिए हमने यहां यह चर्चा रखी है कि अगर वहां लोग जवाबदेह नहीं है तो यहां ससंद के अदंर आप जवाब दें और हमें बाताएं कि ऐसी परिस्थिति को कब तक आप दर करेंगे । इसके अतिरिक्त और कोई वकल्प नहीं है । मैं समझता हूं कि एक गर्वनर जाएगा, दूसरा गवर्नर चला आएगा । 6 महीने तक का कांस्टीटयूशनल मशीनरी टूट जाती है तो हमारे इस महान संविधान के अंदर एक प्रावधान किया गया है कि वहां राष्ट्रपति का शासन लगाकर एक व्यवस्था पैदा की जाए । लेकिन वहां पर क्या होगा जहां कांस्टीटयूशनल मशीनरी के टूटने के नाम पर, एक वैक्यूम पैदा होने के नाम पर राज्यपाल बैठे हुए है, प्रदेश में शासन चल नहीं पा रहा है? ठीक हैं, एक गवर्नर को हटा दीजिए और दूसरे को भेज दीजिएगा, लेकिन हमारा यह आरोप है कि पहली बार केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के बाद वहां लोकप्रिय सरकार नही दे सकी और हमारे केन्द्र सरकार के जो वहां प्रतिनिधि है, वे कहते है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नही आ जाएगा, हम इस सिलसिले में कुछ नही करेगे। संविधान में कई जगह उल्लेख है, सरकारिया आयोग की अगर आप रिपोर्ट उठाकर देखें तो उसमें कई जगह यह सुझाव दिया गया है कि गवर्नर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट नही सकता, उसको छुट नही मिल सकती, अगर किसी वजह से वहां भंग असेम्बली आ गई तो, उसे कोशिश करनी चाहिए । मै यह कहना चाहता हूं कि नेकनीयती से हमारे राज्यपाल महोदय ने सरकार बनाने की कोशिश नही की और जब मैं राज्यपाल की बात करता हूं तो इशार केन्द्र सरकार ने वहां नेकनीयती से कोई प्रयास नही किया । बैठे हुए है साहब, कोई लिस्ट अगर लेकर आयेगा और कहेगा कि हमार बहुमत है तो सरकार बना देंगे और अगर कोई नहीं कहेगा तो ऐसे ही चलने देंगे ।6 महीने के बाद राष्ट्रपति शासन फिर ले आएंगे, 6 महीने गुजर जाएंगे तो फिर राष्ट्रपति शासन ले आएंगे। 17 अक्तूबर को जिस तरह से राष्ट्रपति शासन की पुनरावृत्ति हुई है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में आप कोई अच्छी मान्यताएं नहीं बना रहे हैं। ठीक है,

आपसे पास सत्ता है, आपके पास शक्ति है, हम भी आपका समर्थन कर रहे हैं लेकिन जहां-जहां लोकतंत्र और ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ है, जनता ने उसके खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल किया है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के हितों को देखें। इसलिए अभी भी समय है, सुप्रीम कोर्ट कोई किसी तरीके से बीच में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे इंटरिम आर्डर्स को देखते हुए कोई यह नहीं कह सकता कि अब नया प्रोसैस नहीं शुरू हो सकता, सरकार नहीं बन सकती, अभी भी वक्त है। ये सारी सरकार नहीं बन सकती , अभी भी वक्त है। ये सारी धर्मनिरपेक्ष ताकतें, जो बार-बार साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ आवाज ताकतों से लड़ने का और उत्तर प्रदेश में खास तौर से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और लोकप्रिय शासन देने का, तो ये तमाम ताकतें व्यक्तितवाद की ओर मुड जाती है। हम इनसे खुश है इसलिए सरकार नहीं बनने देंगे, हम इनसे नाराज हैं इसलिए सरकार नहीं बनने देंगे, यह एक गलत स्थिति है। उत्तर प्रदेश के करोड़ो लोग यह सवाल कर रहे हैं, कैसा लोकतंत्र, कैसी पार्लियामेंटरी डेमोक्रैसी, कैसा जनतंत्र, कैसी विधान सभा? हमने वोट दिया है, हमने अपने वोट के अधिकार का प्रयोग किया है लेकिन उसके बाद भी हमको लोकतंत्र का शासन नहीं मिला। आज उत्तर प्रदेश में लोगों से बात करिए तो वहां लोग कहते हैं कि ठीक है, जैसी भी सरकारें थी, ठीक थी क्योंकि वे लोकप्रिय सरकारें थी- विधायक थे, मंत्रीगण थे, मुख्य मंत्री थे। हम उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते थे और उनका समाधान होता था। 100 समस्याएं लेकर जाते थे तो 50 का, 30 का, 20 का समाधान तो होता था।

20 का समाधान होता था, 30 का समाधान होता था। यहां तो कोई बात करने वाला नहीं है। किससे बात करें? अगर इस लोकंतत्र के अदंर, जनतंत्र के अदंर इस प्रकार प्रोक्लेमेशन के जरिए, अध्यादेश के जरिए गर्वनर राज को बढ़ा-बढ़ाकर हुकूमत की गई तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश यकीनी तौर पर वहां पहुंच जाएगा जिसके बारे में आपने इशारा कर दिया है। हमारा प्रदेश टूट जाएगा।यह बहुत बड़ा प्रदेश है। यहां तरह-तरह की मांगे उठती रहती हैं। कभी यह सूवा बनाइए, कभी वह सूबा बनाइए। आज मेरा प्रदेश, जवाहरलाल नेहरू का प्रदेश, लोहिया का प्रदेश, बडे नेताओं का प्रदेश जातिवाद का शिकार हो रहा है। आज अगर जाति और धर्म के नाम पर पोस्टिंग्ज होगी, एस.एच.ओ. आई.ए.एस. अधिकारियों की नियुक्तियों होगी तो निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था तो चरमराएगी ही।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लोग आपसे सवाल कर रहे हैं। केवल हमारी पार्टी सवाल नहीं कर रही है। हमारे प्रदेश के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि कब तक आप हमकों इस परिस्थिति में रखेंगे कि हम जातियों में बेटे रहे, हम धर्म के नाम पर बंटे रहें? हमारी समस्याएं बढ़ रही है। भुखमरी की समस्या बढ़ रही है, अनइम्प्लायमेंट की समस्या बढ़ रही है। वह उत्तर प्रदेश जिस पर हमको गर्व है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया था, आज वह हमारे देश के तमाम राज्यों में सबसे नीचे जाने वाला है। नीचे से हम अव्वल स्थान पर हैं, ऐसा हमें नजर आ रहा है। इसलिए समय रहते हुए चेतिए। अपने निरंकुश राज्यपाल पर अंकुश लगाइए। उसे बताइए कि आपको राजभवन में इसलिए नहीं भेजा गया है कि लोग आप पर अंगुली उठाए। आपको इसलिए भेजा गया है ताकि आप लोगों की समस्याओं का समाधान करें। वहां एक कांस्टीट्यूशन क्राईसिस था, इसलिए वहां पर 356 लगाया गया था। व्यक्तिवाद को घोषित करने के लिए था कुछ राजनीतिक नेताओं े नाम करने के लिए और राजनैतिक हत्याएं हो, इसलिए आपको वहां नहीं भेजा गया है।

महोदय, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि हर राजनीतिक हत्या में, जो बी.जे.पी. के नेता की हत्या हुई है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ है या नहीं। सवाल यह उठता है कि राजनीतिक हत्या हुई है। जब ऐसे लोगों की हत्याएं में लगे हुए हैं तो आम आदमी का क्या होगा? सवाल यह नहीं है कि बी.जे.पी. का नेता मारा गया था समाजचादी पार्टी का मारा गया या कांग्रेस का मारा गया। सवाल इस बात का है कि ये राजनीतिक हत्याएं हो रही है और शासन के रहते हुए हो रही है। इसके बारे में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये हत्याएं बदं होनी चाहिए जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए और सजा दी जानी चाहिए। इन हत्याओं से हमें राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह मानवीय सवाल है। यह हमारे सभ्यता से जुडा हुआ सवाल है, यह हमारे मूल्यों और आदर्शो का सवाल है। आज मूल्यों और आदर्शो के नाम पर वहां अजीब तरह का मजाक हो रहा है।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज वहां जिस तरह से पैसे का दुरूपयोग हो रहा है, जिस तरह से एक व्यक्ति के कहने पर प्रदेश के खजाने का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से हैलीपैड बन रहा है राजभवन के

अदंर, जिस तरह से राजभवन को सजाया और संवारा जा रहा है , जिस तरह से जिम काबेंट पार्क के अदरं नये साल की छुट्टियां मनाने के लिए रिजर्वेशन कराकर केंसिल की जाती है कि जिस तरह से नैनीताल में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है शायद साहिर लुधियानवी जी ने इस वक्त के लिए एक शेर कहा है कि –

"एक शंहशाह ने दौलत का सहारा लेकर,
हम गरीबों की मुहब्बत का उड़ाया है, मजाक।
मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसें" ।

आज उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति हो गई है । माननीय गृह मंत्री जी, तवज्जह दीजिए, प्रधानमंत्री जी तवज्जह दीजिए । एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा मंत्री कुछ करता है । मंत्री जी, हम आपका ऐक्शन चाहते हैं, आपकी ओर से कार्यवाही चाहते हैं। मेरे प्रदेश को बचाइए । देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या का क्षेत्र है, उसको बचाइए । लोकतंत्र के मूल्यों को, लोकतंत्र के आदशों को, गणतंत्र के आदर्शो को बचाइए, कुछ बोलिए, कुछ तो कहिए । धन्यवाद ।

سید سبط رضی اترپردیش: وائس چیرمین صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات رکھوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرارمبھ میں ہی اس بات کو صاف کردوں کہ جب ہم اس پریچرچا میں راجیہ پال مہودے کانام لیتے ہیں تو ہمارا مقصد راجیہ پال پرویکتی گت اکشیپ سے سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔کیونکہ ہم راجیہ پال کو کانسٹی ٹیوشن کے ان پراودھانوں کے تحت یہاں ڈسکس نہیں کرر ہے ہیں۔

جنکے تحت ہم اس ہائی آفس پر بات چیت نہیں کرتے۔ لیکن آج جو ہم یہاں پر چرچا ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پر راشٹرپتی شاسن لگا ہوا ہے۔ اور راشٹرپتی شاسن کے انترگت سنودھان کے انوچھید 356 (ا) (اے)۔ (بی)اولاسن کا اگر خلاصہ لیا جائے۔

میں سدن کا ادھک سمے نہیں لینا چاہونگا کہ انکے پراودھانوں کو آپکے سامنے پرستوت کروں۔ سوئم آپ ا سے بھلی بھانتی جانے ہینکہ جب ہم راجیہ پال کا نام لیتے ہیں اور وہاں آرٹیکل 356 کے تحت راشٹرپتی شاسن لگا ہوا ہے۔ تو پروکلیسمیشن کی گھوسنا کرتے ہی ساری کی ساری ایگزیکٹیو فنکشن کی جتنی بھی ذمہ داریاں اور اختیارات ہیں۔ وہ راشٹرپتی کے ہاتھوں میں شکتیوں نہیت ہو جاتے ہیں تو نشچت روپ سے ہمارا جو فیڈرل سسٹم ہے یا پارلیمنٹری سسٹم ہے اور گورنرمنٹ آف گورنمنٹ ہے۔ اس میں جب جب ہم راشٹرپتی کا نام لیں گے۔ یا راشٹر پتی شاسن کا نام لیں گے۔ یا راجیہ پال کا نام لیں گے تو ہمارا تاتپارئے کیندر سرکار سے ہوگا۔ کیونکہ کیندر سرکار ہی آرٹیکل 356 کے انترگت وہاس پر شاسن چلا رہی ہوتی ہے یہ صحیح ہے کہ راجیہ پال اس کا ایک مادھیم ہوتا ہے۔ اسکا ایک پرتیندھی ہوتا ہے۔ اسلئے اپ سبھا ادھیکش مہودے۔ آج جو پرستھی ہے اتر پردیش میں ابھر آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مکھیہ روپ سے

†[ ]Transliteration in Arabic Script

کھید ہے کہ سنسدئے پرنالی کے انترگت جو ہمیں ادھیکار ملے ہیں- ان ادھیکاروں سے آج جو کیندر سرکار وہاں پرشاسن کر رہی ہے اور انکے جو پرتیندھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں- وہ اس سے ونچت کرنا چاہتی ہے- اپ سبھا ادھیکش مہودے- جس طرح سے مانئے گرہ منتری جی نے بیان کے اوپر پریس کانفرنس کے ذریعہ وکتوئے مہامہم راجیہ پال مہودے نے انکی جو ایگزیکٹیو پوزیشن ہے- اس کا استعمال کرتے ہوئے کیا- اس سے ہم سبھی آہت ہوئے اور یہ جو پارلیمنٹری سسٹم اور گورنمنٹ کی مہان پرمپرائیں ہیں- یا فیڈرل سسٹم کی پرمپرائیں ہیں ان پر اس وقت کافی چوٹ پہنچتی ہے-

مہودے- ابھی جیسا کہ تبصرہ ہمارے لائق دوست نے کیا کہ پائنیر نیوز پیپر میں کل یا پرسوں چھپا ہے گرہ منتری جانتے ہی نہیں ہیں کہ اترپردیش میں کیا ہو رہا ہے- انکے پاس فیکٹس نہیں ہیں- اور جو بھی وہ کر رہے ہیں- اس سے راشٹر بھرمت ہو رہا ہے- میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا 48 سال کا لوک تنتر یا گنتنتر کا جیون ہے اسکے اندر پہلی بار ایسا سنا گیا ہے کہ کیندر سرکار کا پرتیندھی اپنی ہی سرکار- اپنی ہی اغوا اور مکھیا کو کہے کہ انکے پاس اطلاع نہیں کیندر سرکار اسکی ذمہ دار ہے- اگر کیندر سرکار پورن روپ سے وہاں کے پرشاسن میں دلچسپی لی ہوتی تو آج یہ پرستھی نہیں پہنچتی کہ گورنر صاحب کسی غلط فہمی کارن وش یا جانے انجانے میں سنودھان کے یہ جو انوچھیر ہیں- سنودھان کے جو آرٹیکل یا پرویزنس ہیں- انکو وہ یا تو وہ انکو بھول گئے ہیں یا اسکی اندیکھی کر رہے ہیں- اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید وہاں پر کسی ایک ویکتی وشیش کا شاسن ہے یا ایک وشیش راجنیتک پارٹی کا شاسن ہے- یا جو سنکیت مورچہ ہے اسکا شاسن ہے جبکہ اصل میں وہاں پر اس وقت شاسن کیندر سرکار کا ہے- اسلئے اب سبھا ادھیکش مہودے ہم سب چنتت ہو گئے جب لوک سبھا میں ہمارے گرہ منتری جی نے یہ کہا کہ اتر پردیش میں پرشاسن اس حد تک پہنچ چکا ہے- وہاں قانون اور ویوستھا کی استھی اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ وہ اناکری ڈیواسٹیشن پر بربادی کی طرف پہنچ جائیگا- اس سے ہم سبھی آہت ہوئے اور ہم سب کو ایک دھکا لگا اور نسچت روپ سے جب ہم نے ہمارے پردیش کی ایسی استھی پر پریچرچا کی بات کی تو ہمارے ذہن کے اندر ہمارے مانئے گرہ منتری جی کا یہ وکتوے تھا- ہمیں

†[ ]Transliteration in Arabic Script

ہے۔ اب کسی کی غلطی مانی جائے۔ کیا غلطی مانی جائے۔ راجیہ پال مہودے کی کہ وہ کیندر سرکار کو سمے سمے پر جو انکی ذمہ داری ہے وہاں کے حالات پر رپورٹ کرتے رہنے کی۔ وہ رپورٹ نہیں کر رہے ہیں یا وہ رپورٹ کر رہے ہیں تو گرہ منترالیہ اس کے اوپر توجہ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے اوپر دھیان نہیں دے رہا ہے۔ یہ اس پرکار کی ورودھا بھاس کی استھتی آکر کھڑی ہو گئی ہے۔ مہودے۔ میں چاہونگا کہ مانیہ گرہ منتری جی یہاں پر ہیں۔ وہ ہمیں بتائیں کہ اصل میں استھتی کیا ہے۔ آج ہماری ودھائیکا کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی سنسد میں آہوت ہو جاتی ہے۔ جبکہ وہاں ایسی پرستھتی ہے کہ آرٹیکل 356 کا استعمال ہوتا ہے۔ مہودے۔ پہلے یہ پرمپرا تھی کہ جو بھی ودھائی کارئے ہوتے تھے۔ وہ یہاں پر رکھے جاتے تھے۔ اور ان ودھائیکاروں کو دیکھنے کیلئے ایک کمیٹی بنتی تھی۔ جس میں دونوں سدن کے ممبران ہوا کرتے تھے۔ اور وہ نظر رکھتے تھے کیا کیا ودھائیکا کا کارئے ضروری ہے۔ کیا ہونا چاہئے۔ کیا نہیں ہونا چاہئے۔ مجھے کھید ہے کہ ابھی تک اسطرح کی کمیٹی نہیں بنی ہے۔

مہودے۔ یہ کیندر سرکار اترپردیش کو بڑا لائٹلی لے رہا ہے۔ میں یہ آروپ لگانا چاہونگا۔ اترپردیش جنسنکھیا میں سب سے بڑا پردیش ہے۔ اسکی لمبائی نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے اسکی اپنی وبھن سمسیائیں ہیں۔ یہ وہی پردیش ہے جس نے دیش کو آٹھ پردھان منتری دئے ہیں۔ دیش کے وکاس میں دیش کی پرگتی میں اترپردیش کا اپنا ہی یوگدان ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم بھوکے ہیں۔ ہمارے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے۔ ہماری مہیلاؤں کے ساتھ طرح طرح کی ناجائز حرکتیں ہو رہی ہیں۔ میں ان آنکڑوں میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنے لوگ مارے گئے۔ ایک مہینے میں 45 دن میں نو سو لوگ مارے گئے یا کہ 925 لوگ مارے گئے یا یہ پرتیشیت پچھلے سال سے کم ہے یا زیادہ ہے یہ انسانی زندگیوں کے ساتھ آنکڑوں کے اسٹیٹسٹکس کے ذریعہ میں نہیں جانا چاہتا کہ ابھی ہماری وہ حالت نہیں بنی ہے۔ جو پچھلے سال تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھنا تو یہ ہوگا کہ پبلک پرسیپشن کیا ہے۔ لوگ آج کیندرئے شاسن کے بارے میں یا راجیہ پال مہودے کے ذریعہ جو وہاں شاسن چلایا جا رہا ہے۔ کیندر

†[ ]Transliteration in Arabic Script

کے لحاظ سے اسمیں اتر پردیش پچھڑ گیا ہے-گیہوں نہیں مل رہا ہے- راشن نہیں مل رہا ہے- تیل نہیں مل رہا ہے جلانے کا- لوگ تراہیے ترہیے کر رہے ہیں- ان ایمپلائمنٹ ہے- مافیہ گروہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں- راجنیتک انکو پروٹیکشن دیا جا رہا ہے- سنرکشن دیا جا رہا ہے- بہو بیٹیوں کی عزت پوری طرح سے محفوظ نہیں ہے- راتوں کو لوگ گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں- راجنیتک ہتیائیں ہو رہی ہیں- اتیاچار ہو رہے ہیں- ایسی پرستھی میں اگر یہ ہیلی پیڈ بنانے کی بات آئی ہے تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے-

مہودے- بنیادی طور پر جو پردیش کا مکھیا ہوتا ہے- پردیش کی طرف سے جو کام کرتا ہے اسکو ایسا ہونا چاہئے جیسے کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں- اس سرکار میں جو بار بار کہا کرتے تھے ہائی تھنکنگ ہونی چاہئے- اور سمپل لیونگ ہونا چاہئے- آج لوہیا صاحب کے ماننے والے لوگ سرکار میں بیٹھے ہیں جنہوں نے قدم قدم پر یہ آدیش دیا تھا- دیش کو یہ بتانا تھا- اپنی راجنیتک پارٹی کو بتایا تھا- کہ ہمارا آچرن ایسا ہونا چاہئے جو جنتا کہ آچرن سے مل سکے

شاسن کی شکتی لیکر- اسکے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں- آج وہاں ساری جنتا تراہی تراہی کر رہی ہے-

مہودے ابھی یہاں پر بات آئی ہے کہ راج بھون میں ہیلی پیڈ کیوں بنایا جا رہا ہے- بھون کو کیوں سجایا جا رہا ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے- جسکو ہم اٹھانے جا رہے ہیں- ہیلی پیڈ بنتے ہیں بگڑتے ہیں- راج بھون کی فنیشنگ ہوتی ہے- نہیں ہوتی- لیکن بنیادی طور ہماری ایکسپروچ کیا ہے- یہ کہنا راجیہ پال مہودے کا کہ ہم نے ہیلی پیڈ اسلئے بنوایا ہے کہ کافی خرچہ ہوتا تھا- اور اسے پہلے کسی نے سوچا نہیں تھا آج ہم نے سوچ لیا- یہ سوچ کا سوال ہی نہیں ہے- یہ پرورتی کا سوال ہے- مانسیکتا کا سوال ہے- پہلے بھی ہمارے راجیہ پال مہودے جو وہاں ہوا کرتے تھے- وہ سوچ سکتے تھے کہ وہ ہیلی پیڈ ہونا چاہئے- جب ہمارے یہاں استھتی ایسی ہے کہ ہمارے وکاس کا کام رکا ہوا ہے- ہمارا پرگتی کا کام رکا ہوا ہے- ہماری پنچ ورشئے یوجنا پچھڑ گئی ہے ہماری ایک سال کی جو یوجنائیں ہوتی ہیں وہ پچھڑ گئی ہیں- ہماری جو کیپیٹا انوسٹمینٹ ہونی چاہئے- کیندر

†[ ] Transliteration in Arabic Script

جو ہماری زندگی ہے اسکے اندر جنتا کی زندگی کی جھلک آنی چاہئے۔ لیکن ایسا نہیں لگتا۔ لگتا یہ ہے کہ جیسے وہاں کوئی آٹو کریٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے کوئی تانا شاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ راج بھون کے دروازے جنتا کیلئے آج بند ہو گئے ہیں۔ جنتا کی بات تو کیا کہیئے۔ جیسا میں نے پہلے کہا تھا۔ جن پرتیندھی جو ہیں ان کا وہ مہتو نہیں ہے۔ ایک۔ دو۔ چار۔ پانچ جن پرتندھیوں اگر کاکس بنا لیں یا مکھیہ کو گھیر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرستھی جو ہے وہ کچھ بہت اچھی استھی نہیں ہے۔ راجیہ پال جی کو یا کیندر سرکار کو مکھیہ روپ سے وہاں پر جو حالات ہیں انکی طرف توجہ دینی چاہئے۔

مہودے یہ جو بیان آئے ہیں بار بار گرہ منتری کے خلاف یا گرہ منتری نے کچھ اور اسٹیٹمنٹ دیا ہے اتر پردیش کے خلاف اس سے کوئی بہت اچھی استھی نہیں بنتی ہے۔ ہائی آفس پر ہم یہاں پر بحث کر سکتے ہیں۔ یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس ہائی آفس پر بحث نہیں کر رہے بلکہ اس ہائی آفس میں جو بیٹھا ہے پد کی گریما۔ پد کی پرتشٹھا۔ پد کے اقبال۔ راج بھون کی پرمپرائیں راج بھون کے انپیکٹ۔ راج بھون کے اقبال کو جو ہے وہ گرا رہا ہے تو کیسے ہم اس بات کو توجہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف نہ لائیں۔ ہمارا ویکتیگت روپ سے ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا ویکتیگت انکے خلاف کوئی سوال نہیں ہے۔ ہم انکے آچرن پر کوئی آکشیپ یا کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کیندر سرکار سے کہیں کہ وہ چپی توڑیں اور بولیں وہ بتائیں کہ آخر وہاں ہو کیا رہا ہے۔ کیا ایسے ہی ہمارا اترپردیش چلیگا۔ وہاں پر طرح طرح کی سمسیائیں ہیں جو بڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور یہ بدقسمتی ہمارے اتر پردیش کے پچھلے سات آٹھ سال سے چلی آرہی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ایک آدمی کی وجہ سے ہے۔ یا ایک آدمی کی وجہ سے ہے یا ایک پارٹی کی وجہ سے ہے۔ میں ایسا نہیں مانتا ہوں۔ اترپردیش میں کانگریس کا شاسن جانے کے بعد آج ایک استھائتوں کی پرستھی آگئی ہے بڑے بڑے لوگ جو سٹے میں پہنچتے ہیں۔ وہ ایسی غیر ذمہ داری کا پردرشن کرتے ہیں۔ جس سے قانون اور ویوستھا پر اثر پڑتا ہے تو ایسی پرستھی میں ایک ہی وکلپ رہ جاتا ہے کہ کیندر سرکار یہ دیکھے کہ انکا پرتیندھی کہاں پر غلط ہے۔ غلط کارئے کر رہا ہے نرنکش ہو رہا ہے تو اس پر انکش لگایا جائے۔ یدی وہاں ودھان سبھا نہیں ہے تو اسکا

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

بیٹھے ہوئے ہیں اور پرشاسن ٹوٹ گیا ہے- پردیش کا شاسن ٹوٹ گیا ہے- پردیش میں شاسن چل نہیں پا رہا ہے- ٹھیک ہے- ایک گورنر کو ہٹا دیجئے اور دوسرے کو بھیجدیجئے گا لیکن ہمارا یہ آروپ کہ پہلی بار کیندر سرکار اتر پردیش میں چناؤ ہونے کے بعد وہاں لوک پرئے سرکار نہیں دے سکی اور ہماری کیندر سرکار کی جو وہاں پرتندھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ کا ججمنٹ نہیں آجائیگا- ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کرینگے- سنودھان میں کئی جگہ الیکھ ہے سرکار یہ کمیشن کی رپورٹ اٹھاکر دیکھیں- تو اسمیں کئی جگہ سجھاؤ دیا گیا ہے- کہ گورنر اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا- اسکو چھوٹ نہیں مل سکتی- اگر کسی وجہ سے وہاں بھنگ اسمبلی آگئی ہے تو اسے کوشش کرنی چاہئے- میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیک نیتی ہمارے راجیہ پال مہودے نے سرکار بنانے کی کوشش نہیں کی اور جب میں راجیہ پال کی بات کرتا ہوں تو میرا اشارہ کیندر سرکار کی طرف ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیندر سرکار نے وہاں نیک نیتی سے کوئی پریاس نہیں کیا- بیٹھے ہوئے ہیں صاحب- کوئی لسٹ اگر لیکر آئیگا اور کہے گا کہ ہمارا بہومت ہے تو سرکار بنا دیں گے- اور اگر کوئی نہیں کہے گا

مطلب یہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے- آج اترپردیش کے کروڑوں کروڑ لوگ نوکر شاہی سے دبے چلے جا رہے ہیں ایک ایسی بھاونا سے دبے چلے جا رہے ہیں- وچنت ہو رہے ہیں- ان پر یہ کوپربھاؤ پڑ رہا ہے کہ کسی کی کوئی جواب دہی ہی نہیں ہے- جو ہم چاہیں کریں- یہاں پر تو راشٹرپتی شاسن لگا ہوا ہے- یہاں پر تو کیندر سرکار کا شاسن ہے- ایسی پرستھی اچھی نہیں ہے- یدی ودھان سبھا اس وقت وہاں پر نہیں ہے تو کیندر میں ہمارے سنسد ہے- اس کے اندر ہماری سرکار جواب دہی بنتی ہے- اسلئے ہم نے یہاں پر چرچہ رکھی کہ اگر وہاں لوگ جواب دہ نہیں تو یہاں سنسد کے اندر آپ جواب دیں- اور ہمیں بتائیں کہ ایسی پرستھی کو کب تک آپ دور کریں گے- اسکے اترکت اور کوئی وکلپ نہیں ہے- میں سمجھتا ہوں کہ ایک گورنر جائیگا دوسرا گورنر چلا آئیگا- چھ مہینے جب تک کانسٹی ٹیوشن مشینری ٹوٹ جاتی ہے تو ہمارے اس مہان سنودھان کے اندر ای پراودھا کیا گیا ہے کہ وہاں راشٹرپتی کا شاسن لگاکر ایک ویوستھا پیدا کی جائے- لیکن وہاں پر کیا ہوگا جہاں کانسٹی ٹیوشن مشینری کے ٹوٹنے کے نام پر- ایک ویکیوم پیدا ہونے کے نام پر راجیہ پال

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

تو ایسے ہی چلنے دیں گے۔ چھ مہینے کے بعد راشٹرپتی شاسن پھر سے لے آئیں گے۔ چھ مہینے گزر جائیں گے تو پھر راشٹرپتی شاسن لے آئیں گے۔ ۱۷ اکتوبر کو جس طرح سے راشٹرپتی شاسن کی پنرورتی ہوئی ہے۔ اسکے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوک تنتر اور ڈیموکریسی میں آپ کوئی اچھی مانیتائیں نہیں بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپکے پاس ستہ ہے۔ آپکے پاس شکتی ہے۔ ہم بھی آپکا سمرتھن کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں جہاں لوک تنتر اور طاقت کا غلط استعمال ہوا ہے۔ جنتا نے اسکے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جنتا کے ہتوں کو دیکھیں۔ اس لئے ابھی بھی وقت ہے۔ سپریم کورٹ کوئی کس طریقہ سے بیچ میں نہیں آرہا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہاں ہے کہ ہمارا انترم آرڈرس کو دیکھتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب نیا پروسیس نہینشروع ہو سکتا۔ سرکار نہیں بن سکتی۔ ابھی بھی وقت ہے یہ ساری دھرم نرپیکش طاقتیں جو بار بار سامپردائیک طاقتوں کے خلاف آواز اٹھاتی رہتی ہیں۔ لیکن جب وقت آتا ہے سامپردائیک طاقتوں سے لڑنے کا اور اترپردیش میں خاص طور سے سماجوادی۔ دھرم نرپیکش۔ لوک تانترک اور لوک پریئے شاسن دینے کا۔ تو یہ تمام طاقتیں ویکنیواد کی اور مڑجاتی ہیں۔ ہم ان سے خوش ہیں۔ اسلئے سرکار نہیں بننے دینگے۔ ہم ان سے ناراض ہیں اسلئے سرکار نہیں بننے دینگے۔ یہ ایک غلط استھتی ہے۔ اترپردیش کے کروڑوں لوگ یہ سوال کر رہے ہیں۔ کیسا لوک تنتر ہے۔ کیسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی۔ کیسا جن تنتر۔ کیسی ودھان سبھا۔ ہم نے ووٹ دیا ہے۔ ہم نے اپنے ووٹ کے اختیارات کا استعمال کیا ہے۔ لیکن اسکے بعد بھی ہم کو لوک تنتر کا شاسن نہیں ملا۔ آج اتر پردیش میں لوگوں سے بات کریئے تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ جیسی بھی سرکاریں تھیں۔ کیونکہ وہ لوک پریئے سرکاریں تھیں۔ ودھایک تھے۔ منتری گن تھے۔ مکھیہ منتری تھے۔ ہم انکے پاس اپنی سمسیائیں لیکر جاتے تھے اور انکا سمادھان ہوتا تھا۔ سو سمسیائیں لیکر جاتے تھے تو پچاس کا۔ تیس کا۔ بیس کا سمادھان تو ہوتا تھا۔ بیس کا سمادھان ہوتا تھا۔ تیس کا سمادھان ہوتا تھا۔ یہاں تو کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ کس سے بات کریں اگر اس لوک تنتر کے اندر۔ جنتنتر کے اندر اس پرکار پروکلیمیشن

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

یوگدان دیا تھا- آج وہ ہمارے دیش کے تمام راجیوں میں سب سے نیچے جانے والا ہے- نیچے سے ہم اول استھان پر ہیں- ایسا ہمیں نظر آرہا ہے- اسلئے سمے رہتے ہوئے چیتئے- اپنے نرنکش راجیہ پال پرانکش لگائیے- ا سے بتائیے کہ آپکو راج بھون میں اسلئے نہیں بھیجا گیا ہے کہ لوگ آپ پر انگلی اٹھائیں- آپکو اسلئے بھیجا ہے- کہ آپ لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان کریں- وہاں ایک کانسٹی ٹیوشن کرائسس تھا- اسلئے وہاں 356 لگایا گیا تھا- ویکتیواد کو پوسٹ کرنے کیلئے یا کچھ راجنیتک نیتاؤں کے کام کرنے کیلئے اور راجنیتک ہتیائیں ہوں- اسلئے آپکو وہاں نہیں بھیجا گیا ہے-

مہودے میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا کہ اس راجنیتک ہتیا میں جو بی جے پی کے نیتا کی ہوئی ہے- اسمیں کمیونسٹ پارٹی کا ہاتھ تھا یا نہیں- سوال یہ اٹھتا ہے کہ راجنیتک ہتیا ہوئی ہے- جب ایسے لوگوں کی ہتیائیں ہو جائیں جو راجنیتی میں ہیں جو ساماجک کاریئے کرموں میں لگے ہوئے ہیں- تو عام آدمی کا کیا ہوگا سوال یہ نہیں ہے کہ بی — جے- پی کا نیتا مارا گیا یا سماجوادی پارٹی کا مارا گیا یا کانگریس پارٹی کا مارا گیا- سوال اس بات کا ہے کہ یہ راجنیتک ہتیائیں

کے ذریعہ ادھیا دیش کے ذریعہ- گورنر راج کو بڑھا بڑھا کر حکومت کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اتر پردیش یقینی طور پر وہاں پہنچ جائیگا جس کے بارے میں آپنے اشارہ کر دیا ہے- ہمارے پردیش ٹوٹ جائیگا- یہ بہت بڑا پردیش ہے- یہاں طرح طرح کی مانگیں اٹھتی رہتی ہیں- کبھی یہ صوبہ بنائیے کبھی وہ صوبہ بنائیے- آج میرا پردیش- جواہر لال نہرو کا پردیش لوہیا کا پردیش بڑے نیتاؤں کا پردیش- جاتیواد کا شکار ہو رہا ہے- آج اگر جاتی اور دھرم کے نام پر پوسٹنگز ہوگی- ایس- ایچ- او- آئی اے ایس ادھیکاریوں کی پوسٹنگ ہونگی تو نشچت روپ سے قانون اور ویوستھا تو چرمرائیگی ہی-

میں مانیہ گرہ منتری جی سے کہنا چاہونگا کہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں- کیول ہماری پارٹی سوال کر رہی ہے- ہمارے پردیش کے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کب تک آپ ہم کو اس پرستھی میں رکھیں گے کہ ہم جاتیوں میں بنٹ رہے ہیں- ہم دھرم کے نام پر بنٹ رہے- ہماری سمسیائیں بڑھ رہی ہیں- ان ایمپلائمنٹ کی سمسیا بڑھ رہی ہے- وہ اتر پردیش جس پر ہم کو فخر ہے- جسنے سوتنترتا سنگرام میں بہت بڑا

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

ہو رہی ہیں۔ اور شاسن کے رہتے ہوئے ہو رہی ہیں۔ اسکے بارے میں ہمیں گمبھیرتا سے وچار کرنا چاہئے۔ اور یہ ہتیائیں بند ہونا چاہئے۔ جو لوگ اسکے لئے ذمہ دار ہیں انکو پکڑا جانا چاہئے۔ اور سزا دی جانی چاہئے۔ ان ہتیاؤں میں ہمیں راجنیتک لابھ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ یہ مانوی سوال ہے۔ یہ ہماری سبھیتا سے جڑا ہوا سوال ہے۔ یہ ہماری ملیوں اور آدرشوں کے نام پر وہاں عجیب طرح کا مذاق ہو رہا ہے۔

مہودے میں یہ کہنا چاہونگا کہ آج وہاں جس طرح سے ایک ویکتی کے کہنے پر پردیش کے خزانے کا غلط استعمال ہو رہای ہے جس طرح سے ہیلی پیڈ بن رہا ہے راج بھون کے اندر۔ جسطرح سے راج بھون کو سجایا اور سنوارا جا رہا ہے۔ جسطرح سے جم گار بیٹ پارک کے اندر نئے سال کی چھٹیاں منانے کیلئے ریزرویشن کراکر کینسل کی جاتی ہیں۔ جسطرح سے نینیتال میں نیو ائیر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ شاید ساحر لدھیانوی جی نے اسی وقت کیلئے ایک شعر کہا ہے کہ:

ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لیکر
ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق
میرے محبوب کہیں اور ملاکر مجھ سے

آج اتر پردیش میں ایسی استھتی ہوگئی ہے مانیہ گرہ منتری جی۔ توجہ دیجئے۔ ایک منتری کچھ کہتا ہے دوسرا منتری کچھ کرتا ہے۔ منتری جی ہم آپکا ایکشن چاہتے ہیں۔ آپکی اور سے کارروائی چاہتے ہیں۔ میرے پردیش کو بچائیے۔ دیش کا جو سب سے بڑا پردیشن ہے جو سب سے زیادہ آبادی کا چھیتر ہے۔ اسکو بچائیے۔ لوک تنتر کے ملیون کو۔ گن تنتر کے آدرشوں کو بچائیے۔ کچھ بولئے۔ کچھ توکہئے۔ دھنے واد۔ ''ختم شد''

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : इस सदन में उत्तर प्रदेश में कानून और विधि व्यवस्था की गिरावट के ऊपर बहस शुरू हुई है । माननीय विरोधी दल के नेता श्री सिकन्दर बख्त जी ने इस बहस की शुरूआत की । माननीय सदस्य पूर्व गृह मंत्री सैयद सिब्ते रजी का भाषण आप लोगों ने सुना । सवाल उठा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है और उत्तर प्रदेश में वहां के गवर्नर शासन के बदले कुशासन कर रहे हैं ।प्रश्न यह है । राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है । यह बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं । राष्ट्रपति शासन तभी लगता है जब प्रांत का शासन व्यवस्था बन नहीं पाता है । उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दरम्यान चुनाव हुए और चुनावों के बाद जो नतीजे सामने आये उसके लिए दोषी कौन हैं? क्या केन्द्र सरकार दोषी है? हर बात में केन्द्र सरकार को आप दोषी ठहराते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि राष्ट्रपति शासन के बाद विधान सभा के लिए जो चुनाव हुए उस चुनाव के नतीजों के लिए कौन जिम्मेदार है । चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला । ...(**व्यवधान**)...

श्री त्रिलोकी नाथ चुतर्वेदी (उत्तर प्रदेश) : जनता को आप कोसिए । ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती कमला सिन्हा : मैं जनता के पास ही अपील कर रही हूं । ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : कृपया बैठ जाएं, बोलने दीजिए।

श्रीमती कमला सिन्हा : किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सरकार वहां बन नहीं सकी। जो जोड़-घटा-गुणा-भाग जारी रहा उसमें भी कुछ नतीजा निकल नहीं पाया। नतीजा यह कि आज उत्तर प्रदेश में असेबली के रहते हुए भी चुनी हुई सरकार नहीं हैं। पजांब में जो हुआ स्पष्ट तौर पर जनता ने वोट दिया और कहा कि हम वह सरकार चाहते हैं। कश्मीर के वोर्टर्स ने जो मतदान किया और जो नतीजे सामने लाए कि हम यह सरकार चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ होता आज यह हालत नहीं होती। राष्ट्रपति शासन को चालू रखने की किसी भी केन्द्र सरकार की नीयत नहीं हो सकती। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि प्रांतों में हम राष्ट्रपति शासन लागू करें, क्योंकि इससे केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। यह कोई प्रिय घटना नहीं है, कोई सुखद अनुभव नहीं है कि राज्य का बोझ अपने सिह पर रखकर केन्द्रीय सरकार बैठ जाए। आप लोग जो काग्रेंस के साथी है, आप लोगों ने तो सरकार चलाई है। राष्ट्रपति शासन भी बहुत प्रांतों में चलाया है। आपको इसका ज्यादा अनुभव है हम लोगों से। हमारे साथी तो नए-नए साल भर भी नहीं हुआ उन्हें आए हुए। तो आपको ज्यादा अनुभव है उसका। एक पब्लिक सर्वेन्ट होने के नाते इस कठिनाई को मैं समझ सकती हूं। मैं आज राजनीति में नहीं हूं, बहुत लम्बे अरसे से हूं। इसलिए इस कठिनाई को मैं समझ सकती हूं कि आम जनता के अगर चुने हुए प्रतिनिधि न हो तो क्या परेशानी हो सकती है तो मैं यह कहना चाहती थी, कहा गया कि लॉ एंड आर्डर की बहुत गिरावट आई है, यह बात सही है। अखबार उठाकर देखिए, किसी भी प्रांत का अखबार उठाकर देखिए दिल्ली शहर केन्द्रशासित राज्य था एक जमाने में, आज असेंबली है। आप दिल्ली के अखबार को उठाकर देखिए। कौन सा दिन जाएगा कि किसी अखबार में महिलाओं के ऊपर बलात्कार, बच्चों का किडनेपिंग, खून-खराबा न हो। कौन सा दिन है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Mr. Vice-Chairman, Sir, law and order there rests with the Central Government. The Prime Minister, not the Home Minister, »in this House has said that he would look into that situation. The question of law and order in the State still rests with the Central Government. We only want to know why a particular person who failed in Delhi, who failed in Tripura. ...*(Interruptions)* Why is the Central Government showing such a concern for that particular person? ...*(Interruptions)*

SHRIMATI KAMLA SINHA: I am not yielding, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJ1T P.K. JOGI): You speak when your turn comes. Please, take you seat now.

श्रीमती कमला सिंह : तो मैं यह कह रही हूं ...(**व्यवधान**)...

बम्बई – महाराष्ट्र में बी.जे.पी. की सरकार है। पोलिटिकल किलिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, ब्रह्मदत्त दिवेदी की हत्या हुई है। बहुत दुखद बात है, बहुत शर्मनाक बात है। नहीं होनी चाहिए। लेकिन दत्ता सामंत की क्यों हत्या हुई ? मैं ट्रेड यूनियन के साथ जुडी हुई हूं। ट्रेड यूनियन में जो काम करने वाले लीडर्स है उनकी हत्या क्यों होती है, क्यों दत्ता सामंत, की हत्या हुई अनेक लोगों की बम्बई शहर में हत्या क्यो हो रही है। आए दिन? किसी ने प्रश्न पूछा ? आप लोगों ने यह उठाया यह सवाल? अगर उठाया होता तो मुझे खुशी होती। सिकन्दर बख्त जी ने अगर यह सवाल उठाया होता कि दत्ता सामन्त की हत्या एक शर्मनाक हत्या है और बी.जे.पी की सरकार होते हुए भी हत्या हुई और हमें इस बात का दुख है , अगर उन्होंने इस बात को कहा है। मैं किसी की दलाली नहीं कर रही हूं, मैं किसी के बारे में यहां पर ...(**व्यवधान**)... मैं किसी गवर्नर की एडवोकेसी नहीं कर रही हूं। I do know that gentlemen.

लेकिन मैं सीधी-सीधी बात पूछ रही हूं। यह बात कहिए, जो सच्चाई है उसे सामने रखिए लॉ एंड आर्डर की बात उठाई है तो यह कहिए कि सभी प्रांतों में, कहां-कहां लॉ एंड ऑर्डर की गिरावट आई है, उसके बारे में बात कीजिए और सबसे पहले जहां आपके द्वारा शासन चालित है, उन प्रांतों के बारे में बात कीजिए। दूसरे प्रांतों के बारे में बात कीजिए। आज लॉ एंड आर्डर की स्थिति बहुत चिंताजनक है लेकिन मैं बताऊं, यह क्यों हो रही है? इसका सोशियो-इकानॉमिक कारण है। इस देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। नोजवानों की आबादी बढती जा रही है जिनके हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है। हम उनको टेलीविजन पर कज्यूमिरज्म दिखाते

है, आज नहीं दिखा रहे हैं, बरसों से दिखा रहे हैं । ...(**व्यवधान**)...

श्री गोविन्दराम मिरी : (मध्य प्रदेश) उपसभाध्यक्ष महोदय, हम यू.पी. में लॉ एंड आर्डर की चर्चा कर रहे हैं या देश की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : कृपया बैठ जाएं।

This is no point of order.

श्रीमती कमला सिन्हा : इसके कारण नौजवानों के मन में जो चाहत पैदा हो रही है, उसके कारण वे गलत रास्ते पर जाते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तरह-तरह के गलत काम भी करते हैं । यह बात सही है । हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में हत्यांए हुई है । इस देश में राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या से राजनीतिक हत्यांए शुरू हुई । उससे बढ़ कर शर्मनाक हत्या भी कोई हुई है क्या? उससे बढ़ कर शर्मनाक हत्या किसी देश में कैनेडी की हुई, इब्राहिम लिंकन की हुई और उसके बाद भारतवर्ष में हम लोगों ने राष्ट्रपिता गांधीजी की हत्या को देखा । कैसे हुई, किसने किया, किसने नहीं किया, उसको सारा देश,सारी दुनिया जानती है । मैं इसको दोहराने नहीं जा रही हूं । ...(**व्यवधान**)...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : जस्टिस कपूर की रिपोर्ट पढ़िए। पता लग जाएगा । खाली कहने से कुछ नहीं होता।

श्रीमती कमला सिन्हा : इंदिरा जी की हत्या हो गई राजीव जी की हत्या हो गई । हत्याएं आए दिन होती है । हत्या से बाकी बातों को नहीं जोडना चाहिए । मैं जरूर चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रपति शासन समाप्त करके तत्काल वहां के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बने और केन्द्रीय सरकार को निश्चित रूप से इस दिशा में पहल करनी चाहिए । गवर्नर ने गृह मंत्री के बयान पर टीका-टिप्पणी की, यह अशोभनीय बात है । उनको ऐया नहीं करना चाहिए था । गवर्नर को अपने दायरे में रहना चाहिए था । गृह मंत्री ने पूरे देश की शसन व्यवस्था पर नजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा की और जो बात कहीं कई गलत बात नहीं कही । मैं तो सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि वह पूरी व्यवस्था की खोजबीन करे, पूरी बातों की जांच करे और एक रास्ता निकाले । मैं सैयद सिब्ते रजी जी से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश को इस तरह से त्रिशंकु बना कर लटका कर नहीं रखना चाहिए । निश्चित रूप से भी चुने हुए प्रतिनिधि है उनको कहा जाए कि अपनी सरकार बनाओ, चाहे जिसके साथ मिलकर बनाओं । यह मंशा कि हम इनकी शक्ल देखेंगे तो हमें छूत लग जाएगी, इस मनोवृत्ति को हमें मिटा देना होगा और सारे दायरों को भूल कर कि हम चुन कर आए हैं, चाहे जैसे भी चुन कर आए हैं, जनता ने हमें ऐसे ही चुन कर, असेम्बली में भेजा है तो हमें असेम्बली में जुड़ कर , अपने साथियों के साथ हाथ मिला कर एक सरकार बनाने की पहल वहां निश्चित रूप से करनी चाहिए यह मैं सरकार से कहना चाहती हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री बनारसी दास गुप्ता : आपके हाथ में ही सरकार है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : टोका-टोकी मत करिए .... कृपया टोका-टोकी नहीं करें ।

श्रीमती कमला सिन्हा : केन्द्र सरकार से ही मैं निवेदन कर रही हूं कि केन्द्र सरकार को यह तत्काल करना चाहिए ताकि अनिश्चितता का जो वातावरण है उसको समाप्त किया जा सके । उत्तर प्रदेशों में चुनी हुई सरकार बन जानी चाहिए । उसके बाद जो, होगा वह फल भोगेगे। तरह-तरह की बातें सामने आती हैं । "गवर्नर साहब ने अपने घर में, अपने राजभवन में हैलीपैड बनाया है ।" शायद सुरक्षा के लिए, बनाया होगा । "गवर्नर साहब गोल्फ खेलने जाते हैं। मैंने उनको गोल्फ साहब गोल्फ खेलते हुए नही देखो है मैं वहां गयी भी हूं । लेकिन अखबार में या बहुत से लोगों से इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि गोल्फ खेलने जाते हैं ।आप लोगों में से भी बहुत से गोल्फ खेलते होंगे ।

एक माननीय सदस्य : हम नहीं खेलते हैं।

श्रीमती कमला सिन्हा : मुझे नहीं मालूम । इसलिए मैंने कहा है "खेलते होंगे" । गवर्नर होकर गोल्फ खेलना कोई गुनाह नहीं है। अगर वह व्यक्तिगत रूप से गोल्फ खेलते हों तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । किसी कानून में यह नहीं लिखा है कि गवर्नर गोल्फ नहीं खेल सकता । लेकिन राज-काज के समय अगर उसकी अवहेलना करके, सरकारी कार्यो की अवहेलना करके, प्रान्त की अवहेलना करके वह ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से यह चिन्तनीय बात होगी । यह सोचने की बात है । इसलिए सर्वप्रथम बात होगी । यह सोचने की बात है । इसलिए सर्वप्रथम गवर्नर साहब को चेतावनी देनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को आप चुस्त-दुरूस्त कीजिए और उत्तर प्रदेश में अगर अराजकता की स्थिति फैल रही है तो उसको दुरूस्त करो, उसको सुधारों । इसके अतिरिक्त सभी राजनैतिक नेता यहां बैठे हुए हैं । आप सबसे मेरी गुजारिश होगी कि जरा अपने-अपने दल वालों को भी कहिए कि एक-दूसरे की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाए और वहां चुनी हुई सरकार बैठा दें । मुझे इतना ही कहना है । धन्यवाद ।

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Sir, I am feeling very sad that we are discussing Uttar Pradesh—the most populous State in the country. In fact, the population of Uttar Pradesh is even higher than the population of some of the largest countries of the world, like Pakistan or Bangladesh. The State of Uttar Pradesh, which was the cradle of

many civilisations in the past, the State of some of the tallest leaders of our national movement, about whom we take pride, is in a big mess now. I am not saying that this mess has been created over the past few months. There is a long legacy of misrule, mismanagement, neglect and dishonesty by various kinds of political regimes, which the State had to go through. Even today, I understand the literacy rate in the State of Uttar Pradesh is one of the lowest in the whole country. Even with all these big political leaders, there has been very little economic development in the State. I will come to that later. In addition to this, there are all kinds of currents of political opinion in the State. There is communalism of the worst kind which led to the demolition of a historic building, casteism of the worst kind, one caste being but against the other, gang warfare of the worst kind, criminalization of politics of the worst kind, which has put the whole State to shame. Unfortunately, the State, which was a leading State in our country, is now a State which has been put to shame by the way the State has been managed in the past. Now, I agree that the law and order situation is deteriorating. I may not go as far as the Home Minister has gone and had said that there is anarchy in the State. The worrd anarchy is perhaps a very strong word to describe the situation prevailing in the State of Uttar Pradesh. In fact, if you call it anarchy, there had been such a misrule even in the past. There is a long history, as I said earlier. Even then, we feel concerned about many things. For example, we hear about armed robberies in trains, we hear about murders. 1,536 murders in one year had taken place in the State of Uttar Pradesh. It comes to five murders a day, by far the highest in the countrty.

SHRI KHAN GUFRAN ZAHIDI: There were 11,000 murders in one year.

DR. BIPLAB DASGUPTA: That makes it 40 to 50 murders a day which is the highest, in the country. Not only that, there has been killing of a very prominent leader of a particular political party. It does'nt matter to which political party he belongs. It is not important. The important thing is that a very important political leader has been killed. I have also heard about other things. For example, recently in Banaras University four students have been killed. One of them was killed following a certain incident. I am not saying that the University authorities are responsible for this. What I understand is that some slogans were raised in the name of Subhas Chandra Bose, in the name of Nehru and all that. That is fine. But some people wanted to raise a slogan in the name of the Vice-Chancellor, Mr. Hari Gautam. So, they started shouting "Hari Gautam *zindabad"* . One boy refused to shout that slogan and he was murdered. I am not saying that this was the cause. I don't know what the cause was. But the important thing is that when a boy refused to shout a slogan like *zindabad* in the name of the Vice-Chancellor, he was found killed after a few days. This kind of anarchy is prevailing in universities for a long time. The two great universities of our country, the Banaras Hindu University and the Aligarh Muslim University, are now places where hoodlums rule. The vice-Chancellors are incompetent. They cannot run the universities. Taking into account everything, certainly there are instances which show that the law and order situation is not good and certainly there is some evidence of some fear of insecurity in the minds of some people about which we, as a party, are very much concerned. At the same time, I don't like the way in which the Governor is functioning. The Governor has got a certain constitutional position. The Governor has got a certain constitutional position, the Governor is not a political being. The Governor cannot make political statements. The Governor should rule according to the Constitutional norms as also laws and conventions. But here you find a Governor who is issuing Press statements. He may or may not agree

with the statements made by the Home Minister. He may disagree with the statement of the Home Minister, he may sat, "No, there is no anarchy. The Home Minister is wrong." He cannot announce it in the public. His duty is to articuilate his views and grievances to the Home Minister or, maybe, to the Prime Minister, or, maybe, even to the President of the country. How can a Governor hold a Press conference? He even asked the State Chief Secretary to join. Now some of us may be delighied with this. But if the same thing happens in other States, would you accept it? would you permit it? Would you allow the hon. Governor of West Bengal to make such a state-ment? So, it was constitutionally a most improper thing to do. But even worse is this 1 am having a suspicion that the Governor is trying to create a rift between the Prime Minister of the country and the Home Minister of the countrty and, maybe, the Defence Minister also. He is playing politics. It is not his job. The same gentleman was also Governor of Tripura for some time. When he was Governor of Tripura he completely bypassed the State Government. He ran a parallel administration. He had his own coteries of civil servants. They completely defied the rule of the representatives of the people, the elected Government of the State. I feel that as Parliament we cannot allow him. this conduct.

SHRI TRILOKI NATH CHATUR VEDI: He used uncivilised language on telephone .... *(Interruptions)* .....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Please don't mention the conduct of a person ....*(Interrup tions)*.....

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I have a point of information.................*(Interrup tions)*..... I have a point of information. Dr. Biplab Dasgupta is a learned friend of mine and he is related to me as fathei-in-law.

DR. BIPLAB DASGUPTA: The most disobedient son-in-law.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Bihar): He is mentioning about the holding of a Press conference by the Governor and the Chief Secretary together. He may recall that in West bengal the Chief Secretary of West Bengal contradicted a statement of the Prime Minister through a Press conference. So, this is a convention, wherever there is President's rule, the Governor holds a Press conference and through the Press conference informs the people about the developments in the State. There is nothing wrong in it. You can condemn him on the administrative part and not on this part.

DR. BIPLAB DASGUPTA: I don't agree that the Governors can go to the Press.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Conventions are created by your State.

DR. BIPLAB DASGUPTA- When he has a difference of opinion with the Home Minister who is supposed to be his contact person in the Government he cannot voice it if you allow Governors to voice opinions in this way without any discretion, then what will happen to this country? There will be chaos ....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT' P.K. JOGI): Please restrict yourself to the situation in UP.

DR. BIPLAB DASGUPTA: I am talking of the situation in UP. The Sarkaria commission has clearly spelt out how a Governor should function. He should function impartially. He should not function in a partisan manner. He should not take part in politics. This is something which should be adhered to. The conduct of the UP Governor is not commendable. We should not condone his behaviour in Parliament because it will create a constitutional precedent. This will not prove good for anybody.

Now I would like to raise an issue which has not been raised by anybody so far. What about the people of UP? The people of UP have been suffering in many different ways. Certainly, law and order is only one part of it. There are

other economic issues. Sugar-cane growers are not getting a good price for their produce. They are not getting their due share from sugar factories. The recently announced revision in Public Distribution System has not been implemented there. The power situation is bad. The irrigation system is bad. Peasants are suffering. Some of the public sector units, particularly, cement and textiles are sick. They are on the verge of closing down. This is the economic situation which prevails there. Atrocities are committed on women and the Scheduled Castes. This has been happening since a very long time. This is not something new. When we talk of UP, we should take into account the fact that political parties which have been in power in that State in the past helped in the criminalisation and communalisa-tion of politics. They have also not undertaken land reforms. Without land reforms, there can be no solution to the problem of UP. Lastly, I will refer to the political situation. How does one handle the situation in UP? We may or may not be happy with the functioning of the UP Governor. There should be an elected Government. An elected Government should rule the State and not the Governor. But how can we have an elected Government? I would like to put this question to all the major political parties in the country. I am sorry to say this You may or may not agree with me. But there is a saying, Politics makes strange bed fellows. Think of the number of bed fellows different political parties have made in the last two or three years, there have been all kinds of permutations and combinations with no common principle or ideology.

Whether it is the BJP or the Congress party .... *{Interruptions)* ...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Don't say that .... *(Interruptions)* ... Have you forgotten 1977 and 1989? You must remember 1977 and 1989. Congress Party has been the only party which has not done this. Don't talk about all these things .... *(Interruptions)* ...

DR. BIPLAB DASGUPTA: All that the major political parties are interested in is the *kursi.* In order to get that chair, they will sleep with anybody. This is very unfortunate. Politics makes strange bed fellows. That is absolutely correct. This kind of political behaviour has brought discredit to the entire political system. We are not a major political party. Therefore, I would urge upon all the major political parties to consider this matter and find a solution to the problem faced by the people of UP .... *(Interruptions)* ...

SHRI S.S. AHLUWALIA: The language that he has used is very bad. It should be expunged. This should not go on record.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab): What is he talking about bed fellows and all that? .... *(Interruptions)* ...

DR. BIPLAB DASGUPTA: I am withdrawing my words .... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): He has taken back his words .... *(Interruptions)* ...

DR. BIPLAB DASGUPTA: It is an old rhetoric, anybody who claims to know a bit of English should know about it. I have not said anything very offensive. All that I am saying is, that the parties ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Kindly conclude.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Just one sentence. Please allow me to say the last sentence. The parties which are not behaving according to their sense of responsibility, I urge upon them to come to some solution to the political crisis. If all the secular parties can joint together, can form a Government, I will be very happy. I would also be very happy if some State Government of any sort comes about Constitutionally and not through wheeler-dealing, not by buying and selling. 1 would very much like a Govern-

ment tocome about and certainly, if that solution is not possible, may be, there is no alternative but to call elections. In case there has to be a Government of the people for U.P., we should not delay, we should not wait for this, but pending this 1 would urge upon all the political parties who are involved in the State to avoid criminalisation of politics, avoid commun-alism, avoid dishonesty as far as functioning is concerned and to form some ideology. Thank you.

SHRI TRILOKI NATH CHATUR-VEDI: He is calling the little back.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Please sit down.

श्री राजनाथ सिहं "सूया" । आपकी पार्टी का समय खत्म हो गया है । बहुत संक्षेप में बोलिए ।

श्री राजनाथ सिंह "सूर्या" (उत्तर प्रदेश) : श्रीमान, बहुत सी बातें यहां पर कही गई । यह बात वह कर रहे हैं जो दुम्बे बंधे घूम रहे हैं, पार्टी खत्म हो गई है । ...(व्यवधान)... वह समझ गए हैं, काफी समझदार है ।

महोदय, जो बातें कही गई है कि उत्तर प्रदेश में शांति और व्यवस्था किस तरह की है मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता । मैं श्री सिब्ते रजी और हमारे माननीय नेता श्री सिकन्दर बख्त ने जो बातें नहीं है उनको दोहराना नहीं चाहता हूं । लेकिन जो कुछ बातें मुझे कहनी है वह आपको सम्बोधित करते हुए कहनी है इसलिए मैं आपका संदर्भ लेकर एक उदाहरण देना चाहता हूं । आशा है आप में काग्रेंस सदस्य के रूप में चुनकर आए हैं । आप जब यहां बैठते हैं तो उस समय आपका एक प्रकार का व्यवहार होता है लेकिन जब आप इस कुर्सी पर, इस स्थान पर बैठ जाते हैं तो यहां आपका व्यवहार इस आसन के अनुकूल होता है । लेकिन, महोदय, उत्तर प्रदेश में ठीक इसके प्रतिकूल हो रहा है । उत्तर प्रदेश में जो व्यक्ति कुर्सी पर स्टाइल है । राज्यपाल पद को उसने लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि सारे उत्तर प्रदेश में जो व्यक्ति जहां बैठाया जा रहा है, जिस पद पर बैठाया जा रहा है वह उस पद के अनुरूप काम करने के बजाय अपनी लाइफ स्टाइल के अनुरूप उस पदको कन्वर्ट करता जा रहा है और इसका प्रभाव सारे प्रदेश पर पड़ रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक है । कुछ हत्याओं का जिक्र हो रहा है , कुछ ला एंड आर्डर का जिक्र होता है और इसका प्रभाव यह पड़ रहा है कि आज हम यहां बैठकर इस की चर्चा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लड़ा रहा है । जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है दूसरा मंत्री उसकी पीठ ठोक रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो । वैसे तो ला एंड आर्डर उत्तर प्रदेश में कभी अच्छा था ही नहीं । रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जब कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में ला एंड आर्डर की सिचुएशन अच्छी है तो बहुत हद तक मैं उनसे सहमत हूं । सहमत इसिलए हूं कि 1990 में जब वह प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उस समय 48 नगरों में कर्फयू लगा हुआ था । आज 48 नगरों में कर्फयू नहीं है।

श्री रामगोपाल यादव : आपकी पार्टी की कृपा से ।

श्री राजनाथ सिंह "सूर्या" : किसी की कृपा से हो शासन तो आपका था । आपने तो उस समय कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई रेल गाड़ी नहीं जाएगी, उत्तर प्रदेश में कोई पैदल नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश में लोगों को पानी नहीं मिलेगा । माल-गाडियों और बसों को रोक दो । ...(व्यवधान)... आपने उस समय 48 नगरों में कर्फयू लगाया, यही मैं कह रहा हूं । उससे आज स्थिति अच्छी है । अगर मुलायम सिंह जी ऐसा कहते हैं तो ठीक है । यह इसलिए भी ठीक कहते हैं क्योंकि इस समय हाई कोर्ट पर हमला नहीं हुआ । हाई कोर्ट पर नहीं हमला नहीं, किसी कोर्ट पर हमला नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक बात है । इसलिए वह ठीक कहते हैं कि आज जो उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति है, वह पहले से अच्छी है। जब वह यह बात कहते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं । लेकिन आज जिस प्रकार से अधिकारियों से कबूलवा-कबूलवा कर यह बातें कहलवाई जा रही है, यह एटमासफेयर बनाने की कोशिश की जा रही है, यह एटमासफेयर बनाने की कोशिश की जा रही हैं पिछले के दो चार दिनों से जब से गृह मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कह दिया है, यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए बडे जोरदार प्रयत्न हो रहे हैं । एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, ऐक्शन प्लान तैयार किया गया है श्रीमन् मैं आपकी सेवा में एक सूची प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : समय सीमा का ध्यान रखें ।

श्री राजनाथ सिंह सूर्या : बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा । श्रीमन् उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा माफिया गिरोंह की जो सूची आज से एक साल पहले तैयार की गई थी, वह है, और आज यह दावा किया जा रहा है हम माफिया गिरोह की सूची तैयार कर रहे हैं उनको इलीमिनेट करने की कोशिश करेंगे । एक साल पहले तैयार कीगई थी, सही है या गलत है, मैं नहीं कर सकता । किस राजनीतिक दल से कितने गिरोह संबंधित हैं, इसका हवाला भी किया गया है । आपकी इजाजत से पढ़ कर सुना देता हूं । ...(**व्यवधान**)...

श्री ईश दत्त यादव : पहले अपनी पार्टी का बताइयेगा ।

श्री राजनाथ सिंह सूर्या : जी हां, भारतीय जनता पार्टी से ही शुरूआत करूंगा । साढे पांच गिरोह भारतीय जनता पार्टी के साथ संबद्ध बताए जाते हैं ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : यह कैसे ?

श्री राजनाथ सिंह सूर्या : आधा गिरोह आपके साथ और आधा हमारे साथ बताया गया है । ...(व्यवधान)... यह सच है । इलाहाबाद का एक गिरोह है जिसको कहा गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है और कांग्रेस के साथ भी है । कांग्रेस (तिवारी) अब तो रहा नहीं, वह दल भी आपके साथ शामिल हो गया है, इसलिए बाद में उसको भी आपके साथ गिना दूंगा । कांग्रेस साढे पन्द्रह, बी.एस.पी. के साथ आठ । श्रीमन् एक और दल है, जिसको समाजवादी पार्टी के नाम से जाना जाता है, वह 23 गिरोह के साथ संबंधित है । वह बहुत कम है । यह जिले के साथ, किस के विरूद्ध कितने दिनों से मुकदमा कायम है, कब सी.आई.डी. की इन्क्वायरी उनके खिलाफ आर्डर की गई थी, 28-28 साल से सी.आई.डी. इन्क्वायरी हो रही है । ...(**व्यवधान**)...

श्री जितेन्द्र प्रसाद : भारतीय जनता पार्टी के कितने हैं?

श्री राजनाथ सिंह सूर्या : साढे पांच (व्यवधान) वैसे मैं कह दू जो यह बनी है, आप ही के द्वारा नियुक्त राज्यपा का शासन था ...(समय की घंटी)... श्रीमन् मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मैं एक बात पर आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी मुज्जफ्फरनगर कांड में दोषी पाए गए थे जिनके विरूद्ध प्राइम पोस्टिंग लखनऊ जैसी जगह पर दे कर वहां बैठाया गया है । अब यह किस तरफ संकेत करता है? कल यहां पर एक बहस हो गई थी । हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा, मैं बहुत अदब के साथ उनसे कहना चाहता हूं, राजनीति में मेरा उनका बहुत पुरान दोस्ताना संबंध भी है । जब वह सत्ता में बैठते हैं तो उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग सक्रिय हो जाते है, यह बिल्कुल सही बात है, जिनका चरित्र संदिग्ध माना जाता है और स्थिति यह है कि धीरे-धीरे वे अपने राजनीतिक मित्रों को छोड़ कर संदिग्ध चरित्र के लोगों को नजदीक लाते हैं और यही कारण है कि इतनी अधिक राजनीतिक क्षमता का व्यक्ति सत्ता में एक साल, डेढ़ या दो साल से अधिक नहीं टिक पाता है । रामगोपाल जी भले आदमी है, ईश दत्त जी भले आदमी है, और जनेश्वर मिश्र जी भी भले आदमी है, ...(**व्यवधान**)...

श्री रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : हमारी पार्टी में सब भले लोग हैं । जिनका नाम आप ले रहे हैं । आपकी पार्टी से संबंधित होंगे । हमारी पार्टी में सब भले हैं ।...(**व्यवधान**)...

श्री राजनाथ सिंह सूर्या : लेकिन आपके नेता, हम से जो भले आप है, उनके सहारे नहीं है । वह संदिग्ध चरित्र वालों के सहारे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री राम गोपाल यादव : जो संदिग्ध चरित्र के लोग हैं मुख्य मंत्री के सत्ता मे आते ही आपके दल के लोग आस-पास घूमते देखे जाते हैं । अगर वह है तो मुझे कुछ नहीं कहना । ...(**व्यवधान**)...

श्री राजनाथ सूर्या : जो लोग किसी के मुख्य मंत्री बनने के साथ जुडते हैं । वह दलाल ही होते हैं। सत्ता की दलाली इसी को कहते हैं। ऐसे लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तो भले लोग अलग होते जाते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री जितेन्द्र प्रसाद : दलालों की भी कोई लिस्ट है आपके पास?

श्री राजनाथ सिंह सूर्या : बहुत लम्बी लिस्ट है । उसको गिनाने लगूंगा तो वहां प्रिविलेज मोशन मूव हो जाएगा । कहेंगे कि आप संसद सदस्यों का नाम लेते हैं। इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी । श्रीमन् मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देना चाहते , उस के विरूद्ध आपने राजनीतिक तरीके अपनाए ।

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला : लोगों ने नहीं बनाई ।

श्री राजनाथ सिंह सूर्या : ठीक है, लोगों ने नही बनाई ।मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जब आप यह कहते हैं कि जनता के प्रतिनिधियों

की सरकार होनी चाहिए तो जैसे यहां आप ने मिलजुलकर सरकार बनायी । है, वैसे वहां बना क्यों नहीं लेते? आप उत्तर प्रदेश की जनता के साथ यह अन्याय क्यों कर रहे हैं? श्रीमन् मैंने माननीय गृह मंत्री जी को पहली बार देखा है । इस के पहले मेरा उन का कोई संपर्क नहीं रहा, लेकिन मैंने उन की बड़ी प्रशंसा सुन रखी है, मैं उन से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कौन सा ऐसा पाप किया है कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश की जनता पर कहर ढा रहा है । हमें उत्तेजित कर रहा है और आप सब में कुढ़न पैदा कर रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) – कृपया समाप्त कीजिए । अब समाप्त कीजिए ।

श्री राजनाथ सिंह सूर्या : इसलिए आप इस स्थिति को समाप्त कीजिए और राज्यपाल को हटाइए ही नहीं, बर्खास्थ कीजिए ।

श्री जितेन्द्र प्रसाद (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, काफी समय से सभी वक्ताओं के विचार सुने । महोदय, जब यहां उत्तर प्रदेश के बारे में और खासकर उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था के बारे में चर्चा हो रही है तो जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उन से दुख भी होता है, ग्लानि भी होती है और यह भी महसूस होता है कि यह वह उत्तर प्रदेश है जो किसी जमाने में, चाहे वह आजादी की लड़ाई रही हो – बल्कि आजादी के बाद भी इस देश को कई दशकों की दशा दी है । महोदय, आज उत्तर प्रदेश की दशा का जब हम यहां वर्णन करते हैं, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधियों के सामने, तो हमें शर्म भी मालूम होती है । मान्यवर, अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, यह तो सारे विचार आप के सामने आज आ रही है, मगर मेरे दिल में एक प्रश्न यह उठता है कि जब चुनी हुई सरकार काम नहीं कर पाती है तो आप राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, मगर आज हमारे सामने समस्या यह है कि जब राष्ट्रपति शासन आपने लागू किया और वह राष्ट्रपति शासन विफल होता है तब संविधान के अदंर कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम स्थिति को संभाल सके । ऐसी एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति से आज हम गुजर रहे हैं जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए । महोदय, दलगत राजनीति है और हम इस में बहस के जरिए एक-दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं, मगर आज मैं तो यह अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश के हित को देखते हुए हमें जो सच्चाई है, असलिगत है, जो वहां पर कमी है जिस की वजह से आज हम यहां पहूंचे हैं , उस को देखना चाहिए और उस का निराकरण करन चाहिए । यह मेरा निवेदन था ।

महोदय, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था काफी दिनों से खराब है और आज हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं वह तो मैं कहूंगा कि हम चरम सीमा पर पहूंच गए हैं ।मगर उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को खराब करने में, उत्तर प्रदेश के वातावरण को दूषित करने में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने धीरे-धीरे कर के उस गंगा-जमुनी सभ्यता वाले प्रदेश में आज कानून-व्यवस्था को इस हाल में लाकर रख दिया है कि आज दोनों सदनों में ही नहीं बल्कि देश में ही यह चर्चा का विषय बन गया है । मान्यवर, सन् 1992 में जो घटना थी जिस से देश कलंकित हुआ था और कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया था। वह भी एक ऐसी घटना थी जिस ने असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन दिया था। मान्यवर, चुनी हुई विधान सभ के अदंर जिस दिन हमारे प्रतिनिधियों ने हाथपाई की थी, एक-दूसरे के सिर तोडे थे और उस विधान सभा में जिस में बडे-बडे नेता पं0 गोविन्द वल्लभ पंत, संपूर्णानदं सी0वी0गुप्ता और चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्तियों ने इस विधान सभा में नेतृत्व किया था और वहां पर जब लात-घूंसे और खून-खच्चर से लथपथ होकर विधायक निकले थे....

तब भी प्रदेश की जनता को, असमाजिक तत्वों को एक संदेश गया था । असमाजिक तत्व उस घटना को देखकर प्रोत्साहित हुए थे और उसके बाद ऐसी कई घटनाएं घटी, चाहे आप मुजफ्फरनगर कांड को ले लीजिए, चाहे आप हाईकोर्ट पर हमले को ले लीजिए । यह छोटी-छोटी या बड़ी घटनाएं जो हुई, उससे प्रदेश का वातावरण जरूर दूषित हुआ और वातावरण दूषित होने के कारण धीरे-धीरे करके वहां आज कानून व्यवस्था ऐसी बनी, जिस पर आज हम यहां बहस कर रहे हैं ।

मान्यवर, सिकन्दर बख्त जी ने अभी आकंडे सुनाएं । मैं उनको दोहराना नहीं चहता । एक साल के अदंर 11,000 हत्याएं, यह मायने रखती है । आज तक इतिहास में किसी भी साल में 11,000 हत्याओं को रिकार्ड कभी नहीं था । जिस तरीके के लूट, डकैती अपहरण, बलात्कार और दूसरी घटनाएं वहां बढ़ती चली जा रही है, उससे लगता है कि सारी सीमाएं लांघ चुके हैं और इस हद तक पहुंच गए है, जिसका वर्णन हमारे गृह मंत्री महोदय ने किया था। मैं तो उसका समर्थन करूंगा गृहमंत्री जी, जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश कियोस, अनारकी और डिस्टक्शन की तरफ जा रहा है । मैं

आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आपने शब्दशः बिल्कुल सही कहा है । आपने उस हालात का बिल्कुल ठीक ढंग से उस सदन में वर्णन किया है।

मन्यवर, वहां पर क्या हुआ है कि प्रशासन, नेता और माफिया इनका एक गठबंधन बना है और इस गठजोड़ ने सारे तंत्र को तो कमजोर किया ही है, मगर सबसे बुरा काम यह किया है कि इसने इस सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश की है, आज यह गठबंधन आज प्रदेश को सत्यनाश की तरफ बढ़ा रहा है।

मान्यवर, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में एक अजीब वातावरण बना है और वह वातावरण बना है राष्ट्रपति शासन वहां आठ बार लग चुका है । अब जब आठवीं बार यह राष्ट्रपति शासन लगा है तब मालूम यह होता है कि राष्ट्रपति शासन में कहां राज्यपाल जिस तरीके से प्रशासन कर रहे हैं, लगता है कि एक बाई प्रोक्सी रूल वहां कर पर चल रहा है । एक दल राज्यपाल के साथ आज तो खुलेआम है । जिस दिन राष्ट्रपति शासन में वहां लगा था उसी दिन से बाई प्रोक्सी एक दल का राज वहां शुरू हो गया था । जबये यह प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से वहां के हालात बिगड़ने शुरू हो गए। वहां पर किस तरीके से तबादले किए गए कि आए दिन नाम लिया जाता था कि तबादलों की सूची आज दिल्ली से आ रही है । मैं इस सदन मे यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के राजभवन के गलियारों से यह सूचना मिलती थी कि प्रधानमंत्री स्वयं हस्तक्षेप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासन के अदंर । वहां चनु-चुन कर अधिकारी भेजे जाते थे । एक एक दिन में बीस-बीस, तीस-तीस अधिकारियों की सूची निकलती थी । उन अधिकारियों की खासियत क्या होती थी ? कोई करेक्टर रोल नहीं देखा जाता था, उनकी क्षमता नहीं देखी जाती थी बल्कि वह किसके नजदीक है, कौन इनके पीछे है और उसके आधार पर उनकी पोस्टिंग की जाती थी। उसी का आज यह नतीजा है कि वहां की कानून-व्यवस्था आज बिल्कुल ध्वस्त हो गई है । आज एक तरफ तो खुलकर राज्यपाल के हिमायती खडे हैं और दूसरी तरफ राज्यपाल को हटाने के लिए खडे हैं। राज्यपाल को हटाना चाहती है और एक पार्टी राज्यपाल का समर्थन करना चाहती है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की गंभीर स्थिति का राजनीतिकरण किया जा रहा है । उससे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उस समस्या को सुलझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है और यह बहुत गंभीर परिस्थिति है । यह आम चर्चा है, समाचार पत्रों में चर्चा है, आम जनता में चर्चा है कि जिस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश में इस बार बना है, इतिहास में कभी इस तरह का वातावरण नहीं बना। वहां जातीय संघर्ष हो रहे हैं, जिनका वर्णन और माननीय सदस्यों ने भी किया है, साम्रदायिक हत्यांए हो रही है, लूट और अपहरण हो रहे है और स्वचालित हथियारों से राजधानी लखनऊ के अदंर दिन-दहाडे हत्याएं हो रही है । अगर राजधानी के अंदर स्वचालित हथियार लेकर लोग हत्यांए कर सकते हैं तो कल्पना की जा सकती है कि दूर-दराज के और इलाकों में जन-जीवन की क्या स्थिति होगी । लॉ एंड आर्डर की स्थिति टोटली डिमा रलाइज है । अफसर किसी अपराधी के ऊपर हाथ डालने से डरते है। उनको भय है कि अगर हमने इसको छूने की कोशिश की तो, पता नहीं इसको किसका संरक्षण प्राप्त हो, पता नहीं हमें क्या भूगतान पडेगा । आज वहां के अधिकारियों में, लॉ एंड आर्डर मशीनरी में इतनी जुर्रत नहीं है । कि वे अपराधियों पर हाथ डाल सकें, अपराधों में रूकावट कर सकें ।आज वहां अपराधियों के लिए खुली छूट है और जो जितना बड़ा अपराधी है, वह उतना ही बड़ा प्रभावी व्यक्ति है। मेरे विचार में इसका एक कारण यह भी है कि जिस दिन हमने अपराधिक तत्वों को राजनीतिक मंच पर लाकर उकनो सम्मनित किया था, उसी दिन यह तय हो गया था कि इस प्रदेश का वातावरण, इस प्रदेश का सामंजस्य समाप्त हो जाएगा और जिस तरीके का वातावरण हम आज देख रहे हैं, उसकी शुरूआज हम उसी दिन से कह सकते हैं।

मान्यवर, आज प्रदेश का पूरा ढांचा, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे लॉ एंड आर्डर मशीनरी हो, चाहे सामाजिक वातावरण हो, आज पूरा ढांचा चरमरा गया है । यह कहना कि आज वहां लॉ एंड आर्डर नार्मल है, मैं समझता हूं कि इससे गलत बात और कोई नहीं हो सकती । मुझे अफसोस है कि हमारे देश के रक्षा मंत्री महोदय ने, उनका एक-दो दिन पहले दिया गया बयान मैंने आज पढ़ा, कहा है कि प्रदेश में न तो अराजकाता है और न ही आतंकवाद है । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किन तथ्यों को लेकर वो इस बात को कह रहे हैं । राजनैतिक दलों के बयानों से, राज्यपाल के आचरण से यह सिद्ध है कि यह जो विनाशलीला है, राज्यपाल को इस्तेमाल करके प्रदेश के अदंर इस विनाशलीला को बढ़ाया जा रहा है । रूल बाई प्राक्सी, आज

यह सबसे बड़ा कारण है, चाहे हम राज्यपाल को दोषी ठहराएं या राज्यपाल की कार्य-प्रणाली को दोषी ठहराएं । मैं सीधा-सीधा दोष माननीय गृह मंत्री जी आप पर और आपकी सरकार पर लगाना चाहता हूं । राष्ट्रपति शासन अनेक बार लगा है, मगर जिस तरीके से केन्द्र का हस्तक्षेप इस राष्ट्रपति शासन के दौरान हो रहा है, इससे पहले कभी इस तरह का हस्तक्षेप नहीं हुआ । एक-एक के लिए आपका हस्तक्षेप हो रहा है और इस हस्तक्षेप के रहते अगर भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि राज्यपाल को बदलो और राज्यपाल बदल दिया जाता है तो दूसरा राज्यपाल नियुक्त कौन करेगा, आप करेंगे और आपकी सिफारिश पर ही राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा लेकिन आपका हस्तक्षेप यदि इसी तरीके से बना रहेगा तो क्या गांरटी है कि दूसरा राज्यपाल मौजूदा राज्यपाल से भी बदतर न हो जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : वह बात तो है ही ।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : इसको कौन बंद करेगा ? माननीय गृह मंत्री जी इसको आप बदं करेंगे और आपके बयान में और उसके बाद राज्यपाल ने जो बयान दिया और उसके बाद रक्षा मंत्री जी ने जो कहा... (**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Please address the Chair.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : लगता है आप देखना चाहते हैं इनको ।

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहब, मैं ... (**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P. K. JOGI): The Leader of the Opposition wants to say something... *(Interruptions)..*

श्री सिकन्दर बख्त : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने राज्यपाल को बदलने की बात नहीं कही, मैंने उनको बर्खास्त करके वहां कांस्टीटयूशनल सरकार चलाने की बात कही है ।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : बर्खास्त करके कांस्टीटयूशनल सरकार ? राज्यपाल तो बैठाना पडेगा ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Does coming into office of a responsible Government require dismissal of the Governor?

" SHRI SIKANDER BAKHT: Administrative charge goes out of his hands. That is what happens.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: That is different.

SHRI SIKANDER BAKHT: That is not different. That is the most important feature... *(Interruptions)...*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Dismissal of the Governor cannot be a pre-condition for installation of a popular Government.

SHRI SIKANDER BAKHT: I said something; mine was with a rider and that is a popular constitutional Government should be there.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: That is different. The question of a popular constitutional Government is supported by everybody.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Mr. Prasad, you please continue.

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मैं समझा था कि "रिकॉल ऑ दि गवर्नर" , "डिसमिसल ऑफ दि गवर्नर" नहीं है । मैं शायद गलत समझा हूं । जो समाचारपत्रों में मैंने पढ़ा वह "रिकाल" था। मैंने यही समझा कि उनको "रिकॉल" करने का मतलब है कि उनको वापस बुलाया जाए और वहां दूसरा गवर्नर नियुक्त किया जाए । अगर नियुक्ति आपके हाथ में होती तो मैं कुछ सोचता भी । नियुक्ति करने वाले वही है और अगर वहीं हिसाब रहा तो यह हालत सुधरने वाली नहीं है , इतना मैं कहना चाहता हूं ।

जहां तक आपने सरकार बनाने की बात कही है , मैं आज यहां पर कहना चाहता हूं कि अभी कमला सिन्हा जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अदंर किसी का बहुमत नहीं है । वे जनता दल की सदस्य है । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि केन्द्र में भी किसी का बहुमत नहीं था और धर्मनिपेक्षता के सिद्धांत के ऊपर हमने आपको केन्द्र में सत्ता में बिठाया । हमारी संख्या ज्यादा थी और हमारी संख्या ज्यादा होते हुए भी हमारे बलबूते पर आज आप सत्ता में बैठे हुए हैं । हमने आपसे उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले अपील की थी कि धर्मनिपेक्षता के सिद्धांत के ऊपर हमने आपको समर्थन दिया है । अब आपका फर्ज

बनता है कि उत्तर प्रदेश के अदंर आप अपना समर्थन हमको दे और सेक्युलरिज्म के सिद्धांत को मजबूत करें। मगर व्यक्तिवाद, आपसी मतभेद और महत्वकांक्षा के आडे आज उत्तर प्रदेश की बहकिस्मत जनता त्राहि-त्राहि कर रही है।

मैं अब भी अपील करता हूं कि अब भी वक्त है, आप हमको अपना समर्थन दीजिए। हम वहां पर एक मजबूत सेक्यूलर गवर्नमेंट बनाएंगे जिसको 68 फीसदी वोट होगा। कांग्रेस-बहुजन समाज के गठबंधन को युनाइटेड फ्रंट समर्थन दे। वहां पर मजबूत सरकार बनेगी तो हम सिकन्दर वख्त जी को जवाब दे सकेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जाकर कह सकेगे कि हमने एक सरकार बनाई है जो सेक्युलरिज्म के सिद्धांत पर विश्वास करती है। सेक्युलरिज्म के सिद्धांत को आप मजबूत करें।

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश) : हम कांग्रेस से मशविरा लेंगे लेकिन डिक्टेशन नहीं ...(**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : अरे, डिक्टेशन कौन दे रहा है , आपको? आपको कह रहे हैं आईना देखिए, आईने में अपनी शक्ल देखिए। जब 35 को हम समर्थन दे सकते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री वसीम अहमद : यही तो बात है। आप डिक्टेट करना चाहते हैं, ...(व्यवधान)... हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम मशविरा लेंगे ...(**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : आईना देखिए, आईना देखने के लिए कह रहे हैं। उस वक्त हमने नंबर नहीं गिना था। आपसे मशविरा लिया क्योंकि इस देश को सांप्रादायिक ताकतों से बचाना था। फिर यह डिक्टेशना कहां से हो गया?

श्री वसीम अहमद : नहीं, आपने कहा ...(**व्यवधान**)...

श्री एस. एम. अहलूवालिया : तस्वीर देखिए। शीशे में अपनी तस्वीर देखिए।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश की दशा बहुत ही खराब है। विकारा बिल्कुल ठप्प है। किसान हाहाकार कर रहा है। अभी हमारे सी.पी.एम. के साथी ने किसानों की बात की थी। यह बात सही है कि आज किसान हाहाकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश

सरकार एक दाम घोषित करती है किसानों के लिए और उस दाम को नहीं दिला पाती है। महोदय, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट चीनी मिले किसानों को कुछ और दाम दे रही हैं और सरकारी चीनी मिलें कुछ और दाम दे रही हैं। एक जिले के अदंर अगर प्राइवेट चीनी मिले हैं और सरकारी चीनी मिले भी हैं तो वे दोनों किसानों को अलग-अलग दाम दे रही हैं। मैं पूछता हूं कि उन किसानों का कसूर क्या है? इसी सरकार के केन्द्रीय मंत्री दूरदर्शन पर आते हैं और घोषणा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी बहुत चितित है किसानों के लिए। और हम जल्दी-जल्दी एक ऐसा आडिर्निस लाएंगे राज्यपाल से हमने कह दिया है हम आर्डिनेंस लाएंगे ताकि उनको समान भुगतान हो सके। आज इस बात को कहे हुए भी एक महीना हो गया है, आज तक वह आर्डिनेंस नहीं आया। यह पब्लिक के सामने प्रोनाउंसमेंट था। छात्रों पर भी गोलियां चलाई गई। अभी इस पर चर्चा में जिक्र किया गया। पूरे देश के छात्र हाहाकार कर रहे हैं। गोली चल रही थी। एक लड़का भागा। वह भागते हुए छत पर पहुचंता है और दौड़ा करके उसको छत से धकेला जाता है। वह कहता है मैं अपने मां-बाप का अकेला बच्चा हूं। मगर उसको नहीं बख्सा जाता है। छत से धेकलकर मार दिया जाता है। हत्याओं की इतहा हो चुकी है। आम आदमी शाम को निकल नहीं सकता है, घूम फिर नहीं सकता है। इस तरह का वातावरण, अराजकता का वातावरण, अराजकता का वातावरण आज वहां पर बना हुआ है। इन सारी परिस्थितियों की जिम्मेदारी आज केन्द्र सरकार की है। जिस तरीके का इसका आठ महीने का शासन है, इतिहास के अदंर उत्तर प्रदेश में तो हुआ नहीं , मेरा ख्याल है कि देश के किसी भाग में नहीं होगा। मैं केन्द्र सरकार को इसका दोषी मानता हूं। उनसे यह कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति को जल्दी संभाले, नहीं संभालेंगे तो इसका खमियाजा इनको भुगतान होगा। मैं इनको यहां पर चेतावनी भी देना चाहता हूं।

श्री राजनाथ सिंह : समय बतला दीजिए कि कब खमियाजा भुगतान होगा।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : जल्द से जल्द।

यह घोषणा हुई है कि कंसलटेटिव कमेटी बनाई जाएगी। कंसलटेटिव कमेटी मैंने देखी है। मैं मेंबर भी रह चुका हूं। मान्यवर, पार्लियामेंट्री प्रक्रिया की मैं आलोचना नहीं करना चाहता मगर जो मौजूदा परिस्थिति है उससे कंसलटेटिव कमेटी नहीं निबट सकती है, आपको कुछ और करना पडेगा। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि गृह मंत्री जी ने कोई 14 पोंइंट प्लान बनाया है।

मैं तो कहता हूं कि राज्यपाल को आज सोचना चाहिए गृह मंत्री सारे अधिकारियों को बुला करके प्रदेश में कैसे शासन व्यवस्था ठीक की जाए, वह 14 पोइंट का प्लान बनाते हैं। राज्यपाल के बजाए सीधे गृह मंत्री यहां से आदेश देते हैं। यह किस तरफ इंगित करता है क्या यह राज्यपाल की नाकामी की तरफ इंगित नहीं करता है। क्या केन्द्र सरकार का राज्यपाल में विश्वास नहीं रहा है, यह इंगित नहीं करता है। मेरा ख्याल तो इतना ही इशारा काफी थी। अगर समझने वाले नहीं समझेंगे तो यह दुर्भाग्य की बात है।

उत्तर प्रदेश को लेकर के अब यह घिनौनी राजनीति बदं होनी चाहिए। अगर यह घिनौनी राजनीति चलती रही, आपाधापी की राजनीति चलती रही, उत्तर प्रदेश इस समस्या से निकल नहीं पाएगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह कंसलटेटिव कमेटी तो बनती रहेगी और राज्यपाल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मैं आपसे चाहता हूं कि इस सदन में से एक समिति बनाइए और इस सदन की एक समिति तुरन्त लखनऊ भेजिए। वह समाज के सारे वर्गो से वहां मिले मुझे केन्द्र सरकार पर भरोसा नहीं है, यह मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं। समिति को सदन के अदंर बुलाइए और सदन में उस समिति की रिपोर्ट लीजिए और यह सदन तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से कदम उठाने पडेंगे। इस सदन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यह मेरा आपसे आग्रह है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman. In india, there is a democratic system of Government whete the people elect their representatives. The other form of Government is the Presidential form of Government. So far as U.P. is concerned, perhaps, the Presidential form of Government is applicable to that State alone! I say this because, even before the recent elections, President's rule was in force in that State for two-three years. Thereafter, elections took place and the people of U.P. elected their representatives. But it is unfortunate that even after the elections, a representative Government could not be formed in U.P. Why? The Supreme Court has held that the largest party has to be called to form the Government. In such a case, I want to pose one question to the BJP also. The BJP is the largest party in Uttar Pradesh. Suppose that party is called. It does not have sufficient strength, and it is not able to mobilise other parties' support also. Similar is the position of other parties also. There are several parties in Uttar Pradesh. No party wants to see eye-to-eye with the other. The result is that there is no possibility of forming an elected Government in Uttar Pradesh. That seems to be the situation. In such a situation, it is high time the political parties, cutting across their party differences, thought of installing a popular Goernment in Uttar Pradesh.

There is a Governor there. We have seen in the past Governors coming in confronation with the State Governments, but now the Governor is coming in confrontation with the Central Government itself. The Home Minister issued a statement that there was anarchy and lawlessness in Uttar Pradesh. A counter-challenge has been given by the Governor of Uttar Pradesh. Here is a conflict, the Governor challenges the Central Government. The Prime Minister says, "Because of one murder, it cannot be said that the law-and-order situation has worsened there. The Governor cannot be removed." But the Governor is responsible for all these things.

So, it is high time the Central Government removed the Governor from that State. It should see that some peace is restored in that State. I can see from this note that 633 murders took place in January, 1997. There is a report that 959 murders took place. Last year 815 murders took place in Uttar Pradesh. Does any law prevail there? It is said that eleven murders take place daily in Uttar Pradesh. Is there law in force in the country? Is there any power to control. This law lessness? If this is the situation, where will this nation go and where will we go? Something must be done. Here it says that he was the ninth politician killed in the last five years. There is no safety even for politicians or for oersons

working on a public task. If there is no safety for politicians, where is our safety?

There are conflicts between Brahmins and Thakurs. So also between Dalits and others. Likewise, there are clashes between Yadavs and Brahmins. This cast-clash and caste-war is going on. Who has to control this? What is the Central Government doing? The Central Government is not able to control these things in this State. It is the case everywere in the whole of India. Communal murders are taking place in several other States. As a matter of fact, the President's Address says that the internal security is at stake. I am not speaking as an ADMK Member. I am speaking in general. This chaos and confusion is prevailing in all the States, all over India. I would appeal to all the Treasury bench members who belong to the DMK party to hear this. On 5th March, 1996 I had put a question in the House. The answer given: "The overall communal situation in the country has considerably improved since 1993. There was a major communal violence only in one State i.e. in Tamil Nadu during the 1st two months." So, it it is applicable to one State, it is applicable everywhere.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): The discussion is on U.P. So, please restrict yourself to U.P.

SHRI R. MARGABANDU: This is the situation in the whole country. Even Mr. V.P. Singh, the former Prime Minister of our nation was not spared. There was a robbery in his house. Incidents of chain-snatchings, road hold-ups and robberies are common. There is a nexus between politicians and criminals, it has also been admitted by the DSP of that particular State. Even policemen are involved in killings. In such a situation where will the nation go? Therefore, I demand that a situation must be created by the Central Government to ensure that peace prevails and a democratic. Government prevails, bringing about normalcy. Only then will there be a sense of safety in tne minds of the common people and the politicians. Then only can we think of improving the future of our country. With these words, I conclude.

SHRI JOHN F. FERN ANDES: Sir, it is said: "All that begins well, ends well." On 17th of October, 1996, we had completed one year of President's Rule in the State of U.P. Article 356 of the Constitution provides for President's Rule not beyond one year. The President of India had just returned from a foreign tour. On the very same day it was contemplated that a popular Government would be installed there, because the Constitution did not permit further extension of the President's Rule under Article 356 of the Constitution, unless it was amended or vetted by both the Houses of Parliament. I am told a wrong advice was tendered to the President of India based on the 44th Amendment to the Constitution in the light of the judgment of Kerala High Court of 1966.

We claim that this is a federal Government, a Government by the parties ruling in different States. We are also talking about the Sarkaria Commission's Report on giving total autonomy to States, and we have debated this issue several times in the House. Article 356 of the Constitution also says "The President may impose the President's Rule on the advice of the Governor or otherwise." We misuse this article day in and day out and then the Government comes before the Parliament to take the responsibility on itself. I think it will be proper for this House to review Article 356 and give power to the Parliament so that the Government comes to the Parliament before it imposes the President's Rule and not after the President's Rule has been imposed. In case, there is no session of the Parliament going on, it will be appropriate that a special session of the Parliament is called for the purpose.

At the outset I had said that whatever begins well, ends well. The beginning was wrongly made. While vetting the procia-

mation on President's Rule in UP, we had debated this issue. The Allahabad High Court has rightly mentioned aboul it. I do not want to comment on that, because the hon. Leader of the Opposition has already said so. Any student of law more so a Member of this House would know how this article was misused. The matter is being debated before the Supreme Court. Now, we are supporting the United Front Government at the Centre. The President has used his wisdom, his discretion under article 74 because under article 74, at the discretion of the President, he can invite anybody to form the Government. The President has rightly invited the BJP to form the Government. They formed the Government for 13 days. It was well and good. When we discuss about article 356, naturally it has to be read with article 74. Whenever there is a dispute in this Parliament, we refer the matter to the mother Parliament of the United Kingdom. We quote those decisions. So, it would have been appropriate for a Governor of any State to see the political precdent in the country more so, vis-a-vis article *74,* where the President uses his discretion. I don't say that the BJP should have been called. If they had been called, then, they would have formed the government for a week or for not more than 13 days. That is why I am saying for a week. Again there was scope for the Governor to give a chance to other parties to form the Government. If the Government could not decide, then, the duly elected House was there. There was every scope for the Governor to request the House to elect its leader. So what I am saying is that the United Front Government is a contradiction by itself. We have known that just before the election, the Governor was in Tripura. From there he was shunted to Goa. I don't want to say what he did in Goa. They mentioned that he was transferred to Uttar Pradesh. Now, Shri Jitendra Prasad said that he should not be dismissed, but he should be recalled. I hope it is not his intention to say that he should be sent back to Goa because just now we don't have a Governor there. What I am saying is that when we appoint a Governor, that person is usually ridiculed by saying that he is a political appointee, a politician.

Now, we have a former foreign service officer who took orders from the South Block. The Home Ministry is in the North Block. The foreign office is in the South Block. Maybe a Foreign Secretary or an Ambassador is accustomed to get orders from the South Block. The Governor of a State has to take orders from the Home Ministry, North Block. But in the case of Uttar Pradesh, orders are being issued from the South Block. The orders are being given from the PMO. The orders are being issued from the Defence Ministry. I have a note here about the law and order situation in Uttar Pradesh. My other colleagues have mentioned what happened there in a chronological order. The officers are being shunted, honest police officers are being transferred. When the transfers are being questioned, the Raj Bhavan says that orders have come from the PMO. Therefore, what I am saying is that instead of the Governor's office being channelised from the Home Ministry, from the North Block, it is being channelised from the South Block. There is an interference from the South Block.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): The time of your party is almost over. Other speakers of your party would not be called.

SHRI JOHN F. FERNANDES: I will take two more minutes. The office of the Governor is being belittled and that person is being used as an officer-bearer of a political party. The hon. Home Minister has rightly mentioned that there is anarchy in that State. We have seen the anarchy in the tug of war between the Home Minister and the Governor. The Governor of a State cannot go to any other higher authority in the Central

Government except the Home Ministry. We have seen that when this issue of the Uttar Pradesh was being debated in this House, a reply came from the Raj Bhavan, Lucknow. Contradicting the statement of the hon. Home Minister. Again, a statement came saying that the hon. Home Minister would issue a clarification in Parliament. I don't think that clarification has come from the hon. Home Minister, correcting himself, that whatever had been uttered by him was wrong. The Governor had a discussion with the hon. Prime Minister. I do not know if this is not anarchy, what is anarchy? If anarchy is existing at the top, what the Home Ministry is going to do? We say that Article 356 is imposed when there is breakdown of law and order situation in the State. Now, what provision does we have in the Constitution when law and order breaks-down during President's rule? What can the parliament do in such a situation? There is no provision in the Constitution. I think we have to make a provision here that all the functions of that State should be usurped by Parliament. It may be a mini-Parliament, it may be a council of States, because there is no provision in the Constitution. Then the Home Ministry has no solution to that. The Home Minister himself has stated that there is a law and order problem in the State of U.P. There is also a rider in this article. When a Governor has the freedom to give a report, naturally, he will give a report that the situation is not good in the State. The Assembly is in suspended animation. We had the same situation in my State in 1990. the Assembly was in suspended animation. The Congress party had 22 MLAs and the Opposition had 18 MLAs. So, the then Governor—I don't want to name him, we had discussed this issue in the House called the other parties and said: "You defect to the other side," because he was going to invite that party to form the Government. So, two MLAs from the ruling party were taken to the Opposition and a tie of 20:20 was made and a report was sent to the President that he could not install a Government because there was a tie and he could not toss a coin. A report was given to dissolve that Assembly afterwards. This is the gimmick which the Governor sometimes plays agianst the Centre or against the elected representatives of the people of a State, against the will of the people of that State. Therefore, I would suggest that we have to find out a mechanism to deal with such a situation. So, whenever a Governor , because of his self-greed, or greed because he is being dictated from elsewhere, behaves in such a manner, there should be a mechanism to deal with such a situation. Sir, the Home Minister declared the constitution of a Consultative Committee. What purpose will this Committee serve? I would like to know whether the Governor will come before this Committee Can you call a Governor before this Committee? He is the Executive Head, the administratar. He may be a Governor of a State. But under Article 356 of the Constitution, he is the Executive Head also. He is the Chief Minister, he is the Home Minister and he is everything of that State. I do not know what purpose will this Committee serve? Is the Parliamentary Consultative Committee going to consult him? I think the best think the Home Minister can do is to use the Government machinery, and I think, when he made that statement that the law and order has broken-down in U.P., he had consulted the Government machinery, he had consulted the IB and other agencies in the State. So, with these few submissions, I feel the President's Rule is going to expire on 17th of April— the first six months and it will be appropriate that popular parties or secular parties are given a chance to form a Government there. It is all the more essential because the hon. Prime Minister had given an assurance before the elections to the Uttarakhand people that they would get a statehood. When the Con-

gress party said that they would given them a Union Territory, the Prime Minister to score a point over the Congress party, promised them a State, I think this was to deceive the people of that State. Till today, the popular Government has not been installed in U.P. I hope before 17th of April and before the decision of the Supreme Court, a popular Government will be installed in U.P. Thank You.

श्री रामगोपाल यादव : श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा चल रही है और कई सम्मनित सदस्य इस पर बोल चुके हैं । मैं बहुत ध्यान से उनको सुन रहा था, खासतौर से माननीय नेता विपक्ष और माननीय जितेन्द्र प्रसाद जी को । श्रीमन् जब किसी भी राज्य में कहीं कोई हत्या होती है ,लूट होती है और कोई इस तरह की वारदात होती है तो वह दुखद होता है । जब किसी की हत्या होती है तो किसी न किसी मां की गोद सूनी होती है, किसी न किसी बहन का भाई उससे बिछूड जाता है और किसी की मांग का सिन्दूर मिट जाता है । इसलिए जब मैं यह कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था दूसरे राज्यों से बेहतर है तो इसका यह अर्थ न लगाया जाए कि अगर कोई हत्या होती है तो हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं । जब भी अच्छे और बुरे की तुलना होती है तो उसका एक रिलेटिव व्यू लिया जाता है । जब रिलेटिव व्यू लिया जाएगा तो आपको कम्पेयर करना ही होगा कि आज स्थिति क्या है, कल क्या थी, यहां क्या स्थिति है और वहां क्या स्थिति है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के बारे में हिन्दुस्तान के गृह मंत्रालय के जो आंकडे हैं, उनके आधार पर वहां जो स्थिति है वह आपके सामने रखना चाहता हूं । माननीय सिकन्दर बख्त साहब ने बहुत अखबारों की कटिंग पढ़कर सुनाई । मैं नहीं जानता हूं कि अखबारों की कंटिग पूरी तरह आथटिक होती है, सही होती है या नहीं लेकिन मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर कुछ बातें इस माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं और इस अनुरोध के साथ रखना चाहता हूं की अपर हाउस है, यह बहुत गरिमामय सदन है और इस हाउस को पर्सनल ग्रजेज या व्यक्तिगत रंजिश के आधार पर किसी राज्य की पूरी मशीनरी को बदनाम करने की, किसी राज्य के राज्याध्यक्ष और गर्वनर को अपमानित करने तथा हतोत्साहित करने का जरिया या टूल वास्तविकता को नजरांदाज करके नहीं बनाया जाना चाहिए ।

महोदय, उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है । वहां जो पुलिस की स्थिति प्रति 10 हजार पर , 6.17 है । 6.55 बिहार में है, दिल्ली में 37.45 हैं, पंजाब में 24.72 हैं, राजस्थान में 10.48 हैं, महाराष्ट्र में 16.48 हैं और मध्य प्रदेश में 8.69 प्रति 10,000 हैं, अब आप देंखेगे कि सबसे कम पुलिस उत्तर प्रदेश में है । आबादी के आधार पर सबसे कम उत्तर प्रदेश में है । काग्जीनेबल आफेंस के बारे में रिकार्ड होम मिनिस्ट्री ने दिया है । उसके आधार पर स्थिति यह है कि रेट आफ टोटल काग्जीनेबल क्राइम्स जो है, इंडियन पीनल कोड के अतंर्गत उसमें नंबर एक पर दिल्ली है । ....(**व्यवधान**)... मैं आपकी और अपनी बात नहीं कर रहा हूं । मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूं ।

दिल्ली में 434.4 रेट आफ क्राइम है और उत्तर प्रदेश में पर टेन थाउजेंड है 131, राजस्थान में यह 297.9 है, उड़ीसा में 144.51 । महाराष्ट्र में 225.7 , मध्य प्रदेश में 271.1 जो मेजर स्टेटस है उनमें पर टेन थाउजेंड पर जो क्राइम रेट है, इंडियन पीनल कोड के अतंर्गत जो काग्जीनेबल आफेंस है उनमें उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : यह कौन से साल की रिपोर्ट हैं?

श्री रामगोपाल यादव : 1995 की है अब मैं 1996 में उत्तर प्रदेश की स्थिति बताने जा रहा हूं । इससे भी कम है । माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा । 1992 से ले कर 1996 के आंकडे मेरे पास है । उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति अगर सब से ज्यादा खराब रही तो 1992 में रही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां थी । सब से बेहतर जो स्थिति है, वह 1996 की है । मैं बता रहा हूं । डकैतियां 1992 में थी , 1729 और 1996 में 885 (समय की घंटी) आप सुने लीजिए थोड़ी देर इस सदन में अगर लगातार आरोप लगते रहे और दूसरे तरफ निष्पक्ष भाव से सही बात भी नहीं रखी जाएगी? अन्य लोगों का समय समाप्त होने के बाद भी आपने और समय दिया है, मुझे भी दो चार मिनट और दे दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) : आपकी पार्टी का टाइम समाप्त हो गया है । जितना संक्षेप में आप बोल सकते हैं , बोलिए ।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : यह जो फिगर आप कोट कर रहे हैं यह गर्वनर साहब की है या होम मिनिस्ट्री की है?

श्री रामगोपाल यादव : होम मिनिस्ट्री की है, मैं गर्वनर साहब की नहीं कह रहा हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Please continue.

आपका समय हो गया है।

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला : यह जो होम मिनिस्ट्र के स्टेट स्टिक्स कोट कर रहे हैं वह गवर्नर से आए हुए हैं । स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिये हैं । ....(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN: SHRI AJIT P.K. JOGI: Please let him speak. Please continue.

राम गोपाल जी आप बोलिये ।

श्री रामगोपाल यादव : मैं सिंगला साहब से अनुरोध करना चाहता हूं ....(**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : कनफ्यजन सिर्फ इसिलए है कि उनको किताब का नाम कोट करना चाहिए था वह एक इंस्टीटयूट है हमारे देश में जो क्राइम्स का रिकार्ड रखता है कि इसकी परसेंटेंज क्या है । यह किताब लाइब्रेरी में उपलब्ध है ....(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष श्री अजीत जोगी : उनको बोलने दीजिये । आप अपनी बात कहिये यादव जी ।

श्री रामगोपाल यादव : जो रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूं उस पर उनकी आपत्ति हो रही है । अखबार में पढ़ी हुई चीजों को यह अर्थोटिक मान रहे हैं । क्या अखबार में छपी हुई चीज सत्य है । अखबार में यह भी लिखा है कि गवर्नर ने गृह मंत्री की बात को गलत बताया । अखबार में लिखा है कि गवर्नर ने आफिशियली डिनाई किया कि मैंने गृह मंत्री के खिलाफ कोई बात कही थी । यह दोनों चीजें अखबार में हैं । दोनों में से एक चीज जो आपको सूट करे उसको सही मानेंगे । You cannot pick and choose. अभी जितेन्द्र प्रसाद जी कह रहे थे प्रोक्सी रूल चल रहा है । मैं कोई बात ऐसी नही कहना चाहता था । मैं लखनऊ मेल से लखनऊ जा रहा था मुझे मालूम नहीं था, जितेन्द्र प्रसाद जी भी हमारे साथ थे । जब मैं ट्रेन से नीचे उतर रहा था लखनऊ में तो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल खडे हुए थे । मैंने देखा कि वह सुबह 6-7 बजे जितेन्द्र प्रसाद जी को रिसीव करने के लिए खड़े हुए है । वह दो दो दफा गवर्नर रहे है । जब वह ऐसा करने लगें तो क्या ठीक है, कोई मर्यादा, कोई मान्यता कुछ नहीं है । ....(**व्यवधान**)...

मैंने अपनी आंखों से देखा है ।....(**व्यवधान**)...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K.JOGI): He has the right to speak.

श्री जितेन्द्र प्रसाद : भूतपूर्व राज्यपाल मोती लाल वोरा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं । राज्यपाल बनने से पहले वह हमारी पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं और हमारे मुख्य मंत्री भी रहे हैं और कई जगह उन्होंने पार्टी का काम भी किया है । राज्यपाल जब वह नहीं रहे तो पिछले अस्सेबली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने प्रचार भी किया है । मुझे याद नहीं पड़ता कब का जिक्र कर रहे हैं । अगर वह मुझे लेने आ गये जबकि वह राज्यपाल नहीं थे तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है । भंडारी जी जब राज्यपाल नहीं रहेंगे तब आपको लेने आएंगे तो आपको क्या एतराज होगा? ....(**व्यवधान**)...

श्री रामगोपाल यादव : भंडारी जी आपकी पार्टी के लोक सभा प्रत्याशी रहे हैं दिल्ली से । मैं इसलिए कहना नहीं चाहता था राजभवन जिस तरह से वहां बैठ कर लोगों से निर्देश लेता था अगर वह निर्देश न ले तो खराब है अगर उस तरह का निर्देश न ले तो अपनी पार्टी का आदमी होते हुए भी वह आलोचना का केन्द्र बन जाता है ....(**व्यवधान**)... इसलिए अब मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं कहना चाहे तो कह लें, मैं बैठ जाता हूं ....(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Please address the Chair.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : बहुत अच्छा कह रहे हो । ....(**व्यवधान**)... आकंडे नहीं दीजिये । ....(**व्यवधान**)...

श्री गोपाल यादव : श्रीमन्, आकंडे की बात मैं नहीं कह रहा हूं । मै आप से यह कहना चाहूंगा कि सदन के सामने जो तथ्य रखे जा रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि हत्याएं हो रही है, तो हत्या एक भी हो तो खराब बात है लेकिन यह सच है कि पिछले कई वर्षो की तुलना में क्राइम सब से कम है । यह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट और उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट – दोनों की रिपोर्टस में देखा जा सकता है ।

श्रीमन् में इन के इधर बैठे हुए लोगों की बात भी समझ सकता हूं । इन की नाराजगी क्या है, यह मैं समझ सकता हूं, लेकिन श्रीमन् गवर्नर बहुमत नहीं दे सकता । गवर्नर बी.जे.पी. के 214 एम.एल.ए. नहीं कर सकता ।

इन की बात मैं जानता हूं, लेकिन जो जाने-अनजाने बी.जे.पी. के जाल में फंस हरे हैं, उन से मैं यह कहना चाहूंगा कि वे जरा सावधान रहे । उन को ऐसा नहीं करना चाहिए और सोचना चाहिए । ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम बख्श सिंह वर्मा : वह तो आप के जाल में पहले से फंसे पडे हैं ।

श्री रामगोपाल यादव : वह आप के जाल में न फंसे । हमारे जाल में फंसे फिर तो कल्याण है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): You have exceeded your time. Please conclude.

श्री रामगोपाल यादव : इसलिए श्रीमन् मैं सदन के माननीय सदस्यों से आप के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो वास्तविक स्थिति है उस को समझें और केवल अखबार के आधार पर और सुनी हुई बात के आधार पर एकतरफा रूख न बना लें । श्रीमन् उत्तर प्रदेश की मशीनरी, उत्तर प्रदेश की पुलिस हिन्दुस्तान की शानदार पुलिस में से हैं और उत्तर प्रदेश कके आय.ए.एस. हिन्दुस्तान के शानदार आय.ए.एस. में से है । इसलिए पूरी व्यवस्था को एकदम से ऐसा कह देना उचित नहीं होगा । यह तो वह लोग है जिन्होंने 90 में विडियो को नियुक्त कर के यह दिखा दिया था कि गोमती का पानी लाल हो गया है । जब ये यह ब कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात को दूर-दूर किस तरह से दुनिया के सामने रख सकते हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई गुमराह न हो ।

श्रीमन् सही बात और सही तथ्य सदन के सामने हैं और हालांकि ब्रह्मदत्त की बात कल हो चुकी है, मैं कहना चाहूंगा कि वह हमारे दोस्त थे । यह बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या मुंबई और दूसरी जगह सूरत को बदसूरत नहीं कर दिया गया। दत्ता सामन्त की खुल आप हत्या हो गयी और कितनी हत्याएं हो गयी । उसे अगर मैं पढने लगूं तो जनवरी –फरवरी में जितने लोग मुबंई में सारे गए उतने सारे हिन्दुस्तान में नहीं मारे गए । ...(**व्यवधान**)... मैं यह नहीं कह रहा हूं । मैं कह रहा हूं कि वह भी गलत है । मैं यह डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि

(उपसभापति पीठासीन हुई)

आप को सरकार बनाने के लिए गवर्नर न आमंत्रित करे तो इस सदन का सहारा लेकर यह कहें, यह चीज नहीं होनी चाहिए । मैंडम, जनतंत्र में जनता ही सब से बड़ी अदालत होती है । आप सरकार बनाने की कोशिश कीजिए या फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है , अन्यथा वहां दोबारा चुनाव कराए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

मैडम. आप का बहुत-शुक्रिया । धन्यवाद ।

श्री गुफरान जाहिदी : मैडम, मेरा नाम है ।

उपसभापति : आप का नाम नहीं है । आप बैठिए। I have not c.lled your name. I have to go by my list. I am sorry there is a procedure.

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला : मेरा नमा है, मैडम?

उपसभापति : आप का नाम है, सिंगला जी

श्री खान गुफरान जाहिदी : मेरा नाम है पार्टी से ।

उपसभापति : आप का नाम भी जैसे मैं बुलाऊंगी वैसे ही बुलाया जाएगा । अभी आप तशरीफ रखिए । There is a procedure in this House which we have followed. I have to call Shri Gurudas Das Gupta because we have to go by the party. We just cannot call everybody simultaneously.

श्री खान गुफरान जाहिदी : मैडम, मेरा नाम है, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं अन्यथा मुझे यहां खडे होने की जरूरत नहीं थी ।

उपसभापति : आप को खडें होने की जरूरत नहीं है, आप का नाम मेरे सामने है । आप वहां से भी सामने हैं और यहां भी सामने हैं । दोनों जगह सामने हैं । Let me clarify. Your name is in the Short Duration Discussion. Your Party has not given your name.

पार्टी ने नाम नहीं दिया है आप का । अच्छा अभी तो पी.एम. आ गए हैं और चार भी बज गए हैं ।

Mr. Gurudas Das Gupta, please sit down. Now we have the reply on the Motion of Thanks on the President's Address.

श्री राम बख्श सिंह वर्मा : मैडम, अब इसे मंडे को लेंगे?

उपसभापति : हां, मंडे को लेगें । मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ।

4.00 P.M.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I would like to seek one clarification. Will the discussion continue

problems that are being faced by the country. I don't think so. So, let us sincerely evolve a 'situation. Let us try with all honesty and sincerity to review the political situation. Are we in a position to solve these problems without after the hon. Prime Minister conclude his reply or will it be continued on Monday?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't know how much time the Prime Minister will take for his speech. If there is no time today, we can continue the discussion on Monday.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The whole discussion could be completed on Monday.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no problem. We can do that. Now, let his reply be over. Mr. Prime Minister.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS-ONT'D-

THE PRIME MINISTER (SHRI H.D. DEVE GOWDA): Hon. Deputy Chairman, on 20th February, 1997, respected Rashtrapathiji addressed the joint session of both Houses of Parliament. The Address by the President of India is a policy document of the UF Government. We have been governing this country for the last nine months. I don't want to elaborate what achievements we have made in the last nine months. The achievements made by this Government in the last nine months are before the country. The President's Address has clearly indicated the programmes and policies which the UF Government intends to implement during 1997-98. After the President's Address, the General Budget for 1997-98 was also presented to the nation through this Parliament.

Madam, I am not going to minimise the achievements made in the last 50 years. The achievements in the last 50 years cannot be undcrstimated, or cannot be minimised. We are going to celebrate this year the 50ih year of our Independence. The country has progressed in various fields. But, at the same time, the magnitude of the problems before the nation, the problems which our country is facing, I think, will have to be considered in the context of the present political situation. The political atmosphere in this country is so complicated that it is confusing every one. I don't want to elaborate the result of the Eleventh Lok Sabha elections. The people of this country have not given a clear mandate to any political party to run the country. But the United Front has accepted the responsibility of administering the affairs of this country. The United Front is a combination of several parties, with different ideologies, with different manifestos and with different programmes. But all of them have come together and accepted a Common Minimum Programme. All of us have decided to come together and shoulder the responsibility of running the administration of this country. But, for the smooth running of the Government, all of us have to collectively take a decision to narrow down the areas of difference as far as the programmes are concerned. Therefore, we accepted unanimously the Common Minimum Programme. This is like a document of guidelines. It is a sort of indication to the nation as to what we want to do and how we will take this nation forward. We don't want our differences to create any doubt in the minds of the common people of this country who have given us the mandate to maintain our sccular democracy. How best we will be able to exhibit our administrative talent or experience before the nation, is what is of concern to the common man of this nation.

Madam, I would like to spell out what the challenges are, what the